[Shri Dipen Ghosh]

over the papers to him immediately. There is an attempt to doctor the post-mortem report and to influence the forensic report also. It is a serious charge made by her relatives, her colleagues and the association. Mr. Arif Mohammad Khan, Minister of Civil Aviation, should take up the matter immediately with the Delhi Police authoritits and also the Civil Aviation authorities so that the inquiry is not hushed up and the real culprit is taken to task.

SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN (Tamil Nadu): Madam, I want to associate myself with this Special Mention and request the Minister to look into it. Every time this happens with some woman, immediately they say that she was having an affair or that she had a bad character. This is the kind of way these atrocities get suppressed. Therefore, I would also like to join Mr. Dipen Ghosh in calling upon the Minister of Civil Aviation to look into the matter in great detail and see that justice is done.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Look into the matter, Mr. Minister.

THE MINISTER OF ENERGY WITH ADDITIONAL CHARGE OF THE MINISTRY OF CIVIL AVIATION (SHRI ARIF MOHD. KHAN): Madam I will take it up with my colleague, the Home Minister. There is no question of allowing anybody to hush up the matter.

1.00 P.M.

I. RESOLUTION SEEKING APPROVAL OF PRESIDENT'S PROCLAMATION UNDER ARTICLE 356 IN RELATION TO JAMMU & KASHMIR;

II. STATUTORY RESOLUTION SEEKING DISAPPROVAL OF ARMED FORCES (JAMMU & KASHMIR) SPECIAL POWERS ORDINANCE, 1990; AND

III. THE ARMED FORCES (JAMMU & KASHMR) SPECIAL POWERS BILL, 1990—Contd.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Now, we will take up further discussion on the Statutory Resolutions and the Armed Forces (Jammu and Kashmir) Special Powers Bill.

AN HON. MEMBERS: Where is the Minister?

THE DEPUTY CHAIRMAN: He is not here. Mr. Arif Mohd. Khan will be in his place taking the notes. Shri S. S. Ahluwalia to continue.

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया (बिहार) : उपसभापति जी, मैं जम्मू और कश्मीर की आर्म्ड फ़ोर्सेज को स्पेशल पावर देने के लिए जो आर्डिनेंस लाया गया है, उसके विरोध में खड़ा हुआ हूं और मैं जरा याद दिलाना चाहता हूं इस सरकार की कमिटमेंट जो आठ महीने पहले यही सरकार जगह-जगह अपनी बात बड़े जोर पुरजोर से रखती थी।

मैं तो चाहता था कि इस वक्त मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब उपस्थित रहते, तो कम से कम अपने कारनामों को भी जानते, जिसके कारण आज कश्मीर जल रहा है। पर मेरा दुर्भाग्य है और मेरे दुर्भाग्य के साथ-साथ इस मुल्क का भी दुर्भाग्य है कि उन्हें इस बहस को सुनने के लिए भी मौका नहीं है।

महोदया, यह सरकार वह सरकार है जिसने अपने मेनिफ़ेस्टो के माध्यम से सिविल लिबर्टीज की बात की थी और कहा था कि :—

"Under-trials shall be safeguarded from harassment, institutions of Executive Magistrates wherever they exist shall be dispensed with. The UN Convention against torture and those relating to prisoners and refugees shall be ratified and adopted. Suitable prison reforms will be undertaken on a systematic basis."

यह वही सरकार है जिसने ह्यूमन, राईटस की बात कही थी और, महोदया अफ़सोस तो उस वक्त आता है जब मैं कश्मीर के अन्दर सुन्दर घाटियों और वादियों की बात सोचता हूं और समझता हूं कि वहां एक तरफ़ अलगाववादी ताकतें अपनी आवाज बुलंद कर रही हैं। किन्तु जिन पर भरोसा है उन अलगाववादी ताकतों से कोई उनकी रक्षा कर सकता है, तो वह हिंदुस्तान की फ़ौजी वर्दियां पहने हुए सैनिक या अर्ध-सैनिक फ़ौजी वर्दियों में आकर उनकी रक्षा करेंगे। पर आज वह वर्दियां भी कलंकित हो रही हैं और उन वर्दियों में आए हुए वह सैनिक ऐसी वहशत उन पर दिखा रहे हैं—लोग एक तरफ़ अलगावादी ताकतों से आतंकित हैं, परेशान हैं और तकलीफ़ भोग रहे हैं और दूसरी तरफ़ जब वह किसी मदद के लिए उनके पास जाते हैं, तो उनका हर तरह से शोषण होता है।

मैं आपके माध्यम से सदन को याद दिलाना चाहता हूं कि पंचगांव एक छोटा सा गांव है, जिला कुलवाडा में, जहां की आबादी बड़ी छोटी है, पांच हजार की आबादी है और यहां पांच साल पहले जम्मू एंड कश्मीर लाईट इनफ़ट्री का एक पूरा डिवीजन आया था और अस्सी एकड़ जमीन खरीदी गई थी। पर 28 मई, 1990 तक वहां के लोगों को यह पता नहीं था कि इस अस्सी एकड़ जमीन पर कौन रहते हैं। उनको यह पता था कि इस अस्सी एकड़ जमीन पर हमारे देश के सैनिक रहते हैं, हमारे देश के वह सैनिक जो हमारे देश की सुरक्षा, एकता और अखंडता के लिए मर मिटने के लिए तैयार हैं, और हमारे देश की सुरक्षा, एकता और अखंडता को काबिल रखते हैं।

पर उन वर्दियों में कुछ वहशी भी हैं, यह उन्हें पता नहीं था। जो उनके साथ 28 मई, 1990 के बाद जो घटना घटी है, उसके बाद वह इतने आतंकित हैं, इतने परेशान हैं कि उसको अपनी भाषा में बयान नहीं किया जा सकता।

मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं, जो सरकार ह्यूमन राईटस की बात करती है, वह सरकार जो बड़े-बड़े भाषणों में, चाहे वह लाल किले का मैदान हो, चाहे वह राम लीला मैदान हो और चाहे वह पटना का गांधी मैदान हो, इसी सरकार के प्रधान मंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह, राजा विश्व नाथ प्रताप सिंह—उन्होंने अपने भाषणों में यह बातें कही हैं, पर उनकी सुरक्षा नहीं कर सकते।

महोदया, यह घटना 29 मई की है। तीसरे पहर कुछ किसान खेतों की ओर जा रहे थे। जवानों ने उनमें से चार को पकड़ कर पेड़ों पर उल्टा लटका दिया और घंटों तक उनको उल्टा लटका कर रखा और जब वह जवान अब्दुल गणी धर की बीस वर्षीय पत्नी रहमती के घर में घुसे, तो उन्होंने उनकी तलाशी ली और उसको कहा कि तुम मेरे साथ चलो, हम इसकी तलाशी लेते हैं। फ़िर उसके आदमी को भी बाहर दरख्त के साथ बांधकर उल्टा लटका दिया और अन्दर पहुंचकर जो काश्मीरी महिलाएं फ़िरन पहनती हैं, उससे कहा कि यह फ़िरन उठाओ। फ़िरन उठाने का मतलब है कि तुम नग्न हो, तुम नंगी हो, तुम निर्वस्त्र हो और उसके जबर्दस्ती करके, उसके सीने पर बंदूक रख कर उस पर चढ़ बैठे। वह चार महीने की गर्भवती महिला थी और उसके साथ अत्याचार किया। उसके साथ परेशानी की गई और उसके जिस्म के साथ हर तरह के खिल-वाड़ किए इन जवानों ने, महोदया, शर्म आती है। यह मई की घटना है। उसके बाद आज जबकि उनके पास यह पावर नहीं थी, आज हम उसको यही पावर देने जा रहे हैं कि आप ऐसा करें, इसको लीगलाइज करने जा रहे हैं। महोदया, उसके बाद शमीमा पत्नी अली मोहम्मद मिर्जा उर्फ़ खान के घर में दो सैनिक पहुंचे। खान को पकड़ कर गांव की एक दुकान के सामने पेड़ से बांध दिया। फिर चार जवान वापस आए। दो जवान घर के बाहर रुके और दो तलाशी के बहाने

[श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलूवालिया]

शमीम को घर के अन्दर ले गए। अन्दर पहुंचते ही एक जवान ने शमीमा को जमीन पर गिरा दिया और उसके सीने पर बंदूक अड़ा दिया। दूसरा उसके साथ छेड़-छाड़ करने लगा। शमीमा ने विरोध किया और चीख पड़ी। जवानों ने शमीमा को कमरे के अन्दर जाने और अलमारी खोलने के लिए मजबूर किया। इससे पहले कि वह अलमारी खोले उसे गिरा दिया गया। किसी पड़ोसी का दस साल का लड़का वहां सो रहा था। जवानों ने उसे उठा कर बाहर फेंक दिया। जवानों ने शमीमा की सलवार फाड़ दी। उसके मुंह में रूमाल ठूंस दिया ताकि वह चीख न सके और उसके बाद शमीमा के साथ बलात्कार किया गया। इससे ज्यादा शर्म की बात और क्या हो सकती है कि वर्दी पहन कर जवान बिना किसी ताकत के, बिना किसी वारंट के किसी एक कश्मीरी के घर में घुस कर उसकी इस तरह बेइज्जती करें और उसकी महिला, उसकी पत्नी, उसकी बहन, उसकी मां के साथ उसकी अस्मत लेंगें, इज्जत लूटें और हम मूक-दर्शक बन कर इस संसद के अन्दर ऐसे बिल को पास करते हुए देखते रहें? इससे ज्यादा शर्म की बात और क्या हो सकती है? महोदया, इसके बाद जब वह बेहोश हो गई, जब लगातार क्रमवार लोग उसके साथ बलात्कार करते रहे तो वह बेहोश हो गई और वह तब तक बेहोश रही जब तक कि उसका पति जिसे कि पेड़ के साथ उल्टा टांग रखा था और जब आर्मी चली गई तो लोगों ने उसे उतारा और उसके बाद वह जब घर आया तो उसने देखा उसकी पत्नी तब तक बेहोश थी। महोदया, इसके बाद और भी शर्म की बात यह है कि कानून में ऐसे अधिकार हम दे रहे हैं कि साहब, बिना वारंट के ही आप किसी को जा कर पकड़ सकते हैं। यह वाकया 11 जून, 1990 का है। उस दिन लोग वर्ल्ड कप फुटबाल मैच टेलीविजन पर देख रहे थे। वह मैच देखते-देखते रात को पता नहीं किसने गोली चलाई। उसके बाद फौजी वहां पहुंचे और उन्होंने सबको कहा कि घर से बाहर निकलो। जो-जो आदमी हैं, वे सब घर से बाहर निकलो और सड़क पर खड़े हो जाओ। उन लोगों को सड़क पर खड़ा कर दिया गया। महोदया एक परिवार गुलाम रसूल मलिक का था जिसके चार बेटे हैं और दुर्भाग्य से उसके चारों बेटे नेत्रहीन हैं, वह उनकी आवाज सुन कर घर से बाहर नहीं निकल सके। जब जवान उनके घर में दाखिल हुए तो अब्दुल मजीद हनीफ़ा 20 साल, बाबा 22 साल, गुलाम मुगलई बाबा 24 साल और गुलाम मोहीदीन के घर में देख कर उनका पारा और चढ़ गया और जवानों ने बंदूकों के कुंदों से उन सबकी जम कर पिटाई की। एक जवान ने अब्दुल मजीद की आंख में बंदूक की नाल गाड़ते हुए कहा कि यह पाकिस्तानी एजेंट है और अंधा होने का अभिनय कर रहा है। महोदया, इससे ज्यादा शर्म की बात और क्या हो सकती है कि एक हिन्दुस्तानी को जबर्दस्ती पाकिस्तानी एजेंट बनाया जाता है। इस गांव के लोगों ने मजबूर होकर कहा कि आज तक हमें नहीं पता था कि अलगाववाद क्या होता है, मिलिटेंट कौन है, पर आज से इस अत्याचार के बाद हमारा सारा का सारा गांव मिलिटेंट है, क्योंकि हम हिन्दुस्तानी हैं और हमें बंदूक के जोर पर आप हिन्दुस्तानी से पाकिस्तानी बना रहे हैं। हमें जबर्दस्ती कहा जा रहा है कि पाकिस्तानी बनो। महोदया, जवानों ने अब्दुल अहमद मलिक के घर में घुसकर 6 माह की गर्भवती 18 वर्षीय बहिन को जमकर पीटा और सोमबाला वीरा की 15 वर्षीय पुत्री है, चार-पांच जवान उसके कमरे में दाखिल हुए। उन्होंने सदा का हाथ मरोड़ा और उसका झोंटा पकड़ा। एक जवान ने उसके मुंह के करीब बंदूक सटा दी और कहा कि बता गोली किसने चलायी थी? जब सदा ने अनभिज्ञता जाहिर की तो उन्हें पीटा गया। वह चीख पड़ी। उनकी मां ने उसे जवानों के चंगुल से छुड़ाया तो तीन जवानों ने समीना को पकड़ लिया। उसको बेलिबास होने को

कहा । समीना ने उसका विरोध किया तो उसके सीने पर बंदूक तान दी गयी और समीना के साथ एक-एक बार क्रमवार बलात्कार किया गया । उसके बाद.... (व्यवधान)....

श्री शमीम हाशमी (बिहार) : मुफ्ती) साहब कहां हैं ?

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया : मैं चाहता था कि मुफ्ती साहब रहते ।

SHRI SHABBIR AHAMAD SALARIA (Jammu and Kashmir): Neither the Home Minister nor the Minister of State for Home Affairs, nor the Leader of the House is present in the House.

THE DEPUTY CHAIRMAN: The Minister of State for Home Affairs has gone for a meeting. He requested me that till he is not there Mr. Arif Mohd. Khan will take the notes.

डा० अबरार अहमद खान ((राजस्थान) : महोदया, बड़ा महत्वपूर्ण बिल है, लेकिन उसमें गृह मंत्रालय से संबंधित दोनों मंत्रियों में से कोई भी मंत्री नहीं हैं... (व्यवधान)... वह भी बहुत महत्वपूर्ण है । अगर दूसरे काम महत्वपूर्ण हैं, तो यह भी उससे कम महत्वपूर्ण नहीं हैं... (व्यवधान)....यह इस सदन का भी अपमान है कि इस सदन के अंदर गृह मंत्रालय से संबंधित एक बिल चल रहा है, यह इतना महत्वपूर्ण बिल है जिससे एक कानूनी अधिकार मिलने वाला है.... (व्यवधान)...

THE DEPUTY CHAIRMAN: He will take the notes

SHRI SHABBIR AHMAD SALARIA: Mr. Arif Mohd. Khan is not aware of the details of the Home Ministry. It is for the Home Minister to take notes. You will kindly realise the importance of the matter.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Your sentiments have been conveyed. I will ask the Minister for Parliamentary Affairs to inform the Home Minister and the Minister of State for Home Affairs to come.

SHRI GHULAM NABI AZAD (Maharashtra): Madam, we have all respect for Mr. Arif Mohd. Khan, but this is a very important Bill which is being discussed in this House.

SHRI SHABBIR AHMAD SALARIA: This is not a matter to be taken so lightly.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Message has gone. He has sent the message. I will also request the Secretariat to inform the Minister of State for Home Affairs to be here.

श्री हरवेन्द्रसिंह हंसपाल (पंजाब) : मैडम, पार्लियामेंटरी अफेअर्स मिनिस्टर भी तो नहीं हैं, यहां पर, आपने किससे कह दिया ?

उपसभापति : उन्होंने कहा है ।

ऊर्जा मंत्री साथ में नागर विमानन मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : मैंने भेज दिया है ।

THE DEPUTY CHAIRMAN: My Rajya Sabha Secretariat will also do that.

श्री शमीम हाशमी : काश्मीर का चार्ज आरिफ़ साहब आप ले लीजिए । इससे गरीब तो बच । मुफ्ती साहब से तो वह भी नहीं हो रहा है ।

(व्यवधान)

डा० अबरार अहमद खान : आजाद साहब जो आपको बताएंगे, उसको सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि वहां क्या हो रहा है ।.... (व्यवधान)....यह गौर करने वाली बात है । वहां लोगों की इज्जत से खेला जा रहा है.... (व्यवधान)....

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया : महोदया, नसरीम अब्दुल मलिक की बहू है। नबी मलिक पोस्टमैन है। नसरीम अपने पति के साथ घर के बाहर निकली थीं, लेकिन जवान उन्हें घर के अंदर ले आए। अंदर पहुंचने पर उन्हें बिस्तर पर लेटने को कहा। नसरीन ने शोर मचाया। उनके ससुर उन्हें बचाने आए तो जवानों ने उनकी पेशानी पर छड़ी से वार किया। उन्हें धक्का मारकर बाहर निकाल दिया। फिर नसरीम से अपना फ़िरन उठाने के लिए कहा। उन्हें जबर्दस्ती बिस्तर पर लिटाया और जवानों ने उसे निर्वस्त्र किया और उसके साथ छेड़खानियां की। शर्म की बात है। सुबह 4 बजे घर का दरवाजा खटखटाया गया तब हाजी अजीजा बेगम.. (व्यवधान)....

I am coming to that.

SHRI SHABBIR AHMAD SALARIA: We do not expect it to happen in your regime what was happening in their time. ..

DR. G. VIJAYA MOHAN REDDY (Andhra Pradesh): We condemn that.

SHRI SHABBIR AHMAD SALARIA: You should control that. We want that you should not alienate the people. (*Interruptions*).

THE DEPUTY CHAIRMAN: I think your name is with me on the list. I will permit you to take your time to speak. Please do not interrupt. Let him finish.

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया : महोदया, मैं पहले भी कह चुका हूं, फिर कहता हूं कि यह जो कह रहे हैं कि यह हमने पाले हुए हैं, यह हमारे पाले हुए नहीं हैं। आपने अपने मेनीफेस्टो में कहा है। जो आपने साल्यूशन पालिटिकल प्रोब्लम दिया है, उसमें काश्मीर का नाम नहीं है। काश्मीर की प्राब्लम आपकी पैदा की हुई है। आपने तैयार किया है। यह आपका मेनिफेस्टो कहता है। इस मेनिफेस्टो में आपने पंजाब, आसाम, रामजन्मभूमि-बाबरी मस्जिद के बारे में कहा था, कश्मीर के बारे में नहीं। आप अपने मेनिफेस्टो को पढ़ें। उस वक्त काश्मीर में कोई प्रोब्लम नहीं थी। मिस रूबिया के अपहरण का ड्रामा रचाकर आपने पांच खूंखार आतंकवादियों को छुड़वाया और सारा ड्रामा करवाया। उसके बाद से यही सब हो रहा है।

महोदया, सुबह चार बजे घर का दरवाजा खटखटाया गया। तब हाजी अजीदा बेगम सो रही थीं और उनके बेटे गुलाम मोहम्मद ने दरवाजा खोला। एस० एल० आर० बंदूकों से लैस पन्द्रह जवान अंदर दाखिल हुए। पुरुषों को घर के बाहर ले जाया गया। एक जवान ने अजीदा बेगम से पूछा कि फैरन के अंदर क्या छुपाया है। उन्होंने बताया कि मैं नौ माह की गर्भवती हूं, मेरी एडवांस स्टेज है, डज प्रिगनेन्सी की, नौ माह की गर्भवती हूं, इसलिए पेट फूला हुआ लेकिन जवान उनकी बात मानने को तैयार नहीं हुए, वे अड़े हुए थे कि अजीदा बेगम ने जरूर कुछ छिपाकर रखा है और जवानों ने उसे कपड़े उतारने के लिए कहा। उसके कपड़े उतारे गए और उसके पेट को दबादबा कर टटोला गया, उस गर्भवती महिला को परेशान किया गया, हर तरह से उसके साथ बदसलूकी की गई। इससे ज्यादा शर्मनाक बात और क्या हो सकती है?

महोदया, बात यहीं खत्म हो जाती तो मैं शांत हो जाता। यह कुपवाड़ा गांव है। उस गांव में करीब 35 परिवार पंडितों के थे और वे पंडित वहां के हालात खराब होने पर वहां से बाहर चले आए, लेकिन वहां के मंदिर की चाबियां आज भी वहां के मौलवी के पास हैं और उन 35 घरों का एक तिनका भी कोई उठाकर नहीं ले गया। उस मंदिर की सेवा वहां का मौलवी करता है और जो सभी गांव

छोड़ चुके हैं, उन सभी के घरों की चाबियां गांव के मौलवी के पास है। यह 22 अप्रैल का शबेबरात था, लोग इबादत की सुबह साढ़े पांच बजे ईदगाह से निकल रहे थे। तभी सेना के जवानों ने सबको घेर लिया और बच्चों, जवानों और बूढ़ों को अलग-अलग हिस्सों में बांट दिया। उनमें हाज अफजल अहमद शाह भी थे। उन्होंने बताया कि मुझसे जयमाता और जय हिंदुस्तान कहलवाया गया। श्री शाह ने कहा कि जबसे कश्मीरी पंडित यहां गांव छोड़कर गए हैं, मैं ही मंदिर की धुलाई-सफाई करता हूं, हम कश्मीरी ऋषियों और मुनियों के बन्दे हैं, हमने सभी धर्मों और पूजा-स्थलों का सम्मान करना सीखा है। अब्दुल रहमान के साथ भी यही हुआ। उन्होंने बताया कि मैं जम्मू-कश्मीर पीपुल्स कांफ्रेंस का कार्यकर्ता हूं, मैंने बंदूक की खौफ के बिना भी हजारों बार हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए हैं, मैंने हजारों बार बंदूक के दबाव के बिना भी हिंदुस्तान-जिंदाबाद कहा है, लेकिन मेरी छाती पर जवानों ने बंदूक रखकर कहा कि जय-माता की और हिंदुस्तान-जिंदाबाद कहो तभी जिंदा रहोगे, नहीं तो मार डालेंगे। इस तरह की शर्मनाक बातें हो रही हैं।

महोदय, इसके बाद 9-10 जून रात को पूरे गांव की तलाशी लेने के बाद जवानों ने तमाम औरतों को एक जगह जमा किया और एक युवक, जो उस गांव का जवान युवक था, उसके कपड़े उतरवाए और उस युवक को नग्न करके बंदूक की नोंक पर कहा कि अपने इस गांव की, महिलाओं को कहो कि मेरी तरफ देखो मैं नग्न हूं, मेरी तरफ देखो। उस गांव की महिलाएं शर्म से सिर नीचे किए हुए थीं, वे देख नहीं सकती थीं क्योंकि किसी का वह भाई था, किसी का देवर था, किसी का बेटा था, किसी का वह जीजा लगता था। लेकिन उन सारी औरतों को मजबूर करके कहा गया कि वे उस नग्न लड़के को देखें और अगर नहीं देखेंगी तो उसे गोली मार देंगे। बार-बार जवान उस युवक से कह रहे थे कि तुम्हें देखें और जब युवक ने उनके आदेश का पालन किया तो जवान महिलाओं से कह रहे थे--जाओ, इससे अपनी आजादी ले लो।

इससे ज्यादा शर्म की बात क्या हो सकती है, महोदया, कि जिस समाज में हम संसद में बैठकर बड़े-बड़े कानून बनाते हैं, जिस समाज में हम अपनी इज्जत और अस्मिता की रक्षा नहीं कर सकते, जिस समाज में हम अपने ह्यूमन राईट्स की बात नहीं उठा सकते, जिस समाज में एक मां और बेटे के साथ, एक बहन और भाई के साथ व्यभिचार करने के लिए मजबूर किया जाता है बंदूक की नोंक पर, उससे ज्यादा शर्म की बात क्या हो सकती है ?

महोदया, इसकी शुरूआत, मुफ्ती साहब यहां नहीं हैं, जिन्होंने की थी। उस दिन जब मैं बोल रहा था तो उधर से चिल्लाकर अफजल मियां ने कहा था कि जरा, हुनसे पूछो, कांग्रेस क्या कर रही थी ? सन् 1975 से 1987 तक वहां पी०सी०सी० प्रेसिडेंट मुफ्ती साहब थे, उन्होंने यह पैदाइश की है। इतना ही नहीं, काजी निसार, जो उनका रिश्तेदार है, इस रिश्तेदार को एन० यू० एफ० का अध्यक्ष बनाया और आज उसकी जान बचाने के लिए उसे जेल में रखा हुआ है एन० एस० ए० में बंद करके। एन० एस० ए० में बंद करके और इस तरह से यह राजनीति करते रहे। महोदया, मैं कोट करना चाहता हूं एक कोटेशन को। जब हम एक बिल पास कर रहे थे तो हमारे एक विपक्ष के नेता ने बहुत लम्बे-लम्बे भाषण दिए थे। मैं उसको कोट करना चाहता हूं :

"I am talking of the whole House—the whole House from that end to this end gave the powers to deal with the issue of Punjab. It is not a question of giving more and more powers. More power to a powerless Government is no-

[श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया]

thing. Any number when multiplied by zero will always give zero We may give all the powers. But that gets multiplied by zero. That is the problem, Madam. And if a law were to be brought, it is not this law. I think we should have a law against the incompetence of the Government. Unfortunately we do not have that. It is the final verict of the people that will give that verdict on this. But this is what we have come to .

But, apart from this, Madam, it is the thrust of the solutions that are sought which, to my mind, is more a basic issue of political debate and how this Government wishes to handle this situation of Punjab. The thrust is towards more gun-powder, more bullets, more bayonets. Bullets will not generate brotherhood. This is the thrust I am more afraid of. One Draconian law, one coercive law, one coercive action has a compulsion of another coercive action and a still more coercive action. And we have come to the final coercive action—of suspending the right to life also. That is the final thing we have come to."

महोदया, जानकर आश्चर्य होगा कि यह भाषण किसने दिया था ? आज यह इसी निकम्मी सरकार का प्रधान मंत्री है—राजा विश्वनाथ प्रताप सिंह, जिसने इसी सदन में यह भाषण दिया था और जिसने ह्यूमन राईट्स की बात कही थी पंजाब के मसले पर, परन्तु आज वही राजा विश्वनाथ प्रताप सिंह क्या बिल लाता है ? . . . . (**व्यवधान**) . . . .

श्री सत्य प्रकाश मालवीय (उत्तर प्रदेश) : उपसभापति जी, एक दिन जब अहलुवालिया जी ने इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया था तो आपने व्यवस्था दी थी कि कम से कम सदन के अंदर ऐसी भाषा का प्रयोग करें और सदन की गरिमा के अनुरूप हो । इस वाक्य में, जो उन्होंने प्रयोग किया है प्रधान मंत्री के लिए, मेरी समझ में वह असंसदीय है । मेरा आपसे एक तो आग्रह यह है कि . . . . . (**व्यवधान**) . . . .

श्री आरीफ मोहम्मद खान : माननीय उपसभापति जी, मेरा तो निवेदन यह होगा कि रहने दीजिए रिकार्ड में ताकि देश के लोगों को पता चले कि माननीय सदस्य कैसी भाषा का प्रयोग करते हैं ।

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया : जरूर । जी हां ।

श्री आरिफ मोहम्मद खान : लेकिन निश्चित तौर पर यह भाषा इस सदन की परम्परा, इस सदन की गरिमा, हमारी जो पुरानी रिवायतें हैं उसके अनुरूप नहीं है ।

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया : कौन सी भाषा गलत कही मैंने, आप बताएं ।

श्री आरिफ मोहम्मद खान : आप रिकार्ड को देख लीजिए, आपको अंदाजा हो जाएगा । मैं कहता हूं कि किसी बात पर भी मतभेद हो सकते हैं, गंभीर मतभेद हो सकते हैं लेकिन उसके लिए यह जरूरी नहीं है कि मतभेद बताने के लिए उस भाषा का प्रयोग किया जाए जो शालीनता से गिरी हुई हो ।

SHRI SHABBIR AHMAD SALARIA: Madam Deputy Chairman, half an hour is past but the Minister has not yet come.

THE DEPUTY CHAIRMAN: He will come.

SHRI SHABBIR AHMAD SALARIA: He will come and by that time...

THE DEPUTY CHAIRMAN: There are many other speakers also.

आप बैठिए । आप रहेंगे । मैंने उनको बुलवाया है, मैसेज भेज दिया है और मैं अहलुवालिया जी से भी कहूंगा कि आप गम्भीरता से एक विषय पर बोल रहे हैं, आप ऐसी भाषा का इस्तेमाल करें जो इस सदन की शायानिशान हो । हम फुटपाथ पर नहीं बैठे हैं, सड़क पर नहीं बैठे हैं, हम इस हाउस में बोल रहे हैं और अहम मसलों पर बोल रहे हैं । इसलिए अगर आप अच्छी भाषा का इस्तेमाल करेंगे तब भी आप जो कहना चाहते हैं, वह कह सकते हैं ।

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया : महोदया, मैं आपकी बात पर ही आता हूं। क्या मैंने फुटपाथ की भाषा का प्रयोग किया है ?

उपसभापति : फुटपाथ का मतलब नहीं है । आप किसी से यह. ... **(व्यवधान)**....

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया : नहीं, आपने फुटपाथ की बात कही है ।

उपसभापति : अब आप बहस में न जाएं।

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया : आप अगर मेरी भाषा पर कहती हैं, मैं आपकी भाषा पर कहता हूं । आपने फुटपाथ की बात क्यों कही ?

उपसभापति : आप अगर चुप रहें तो मैं आपको बताऊं । आप एक मिनट बैठेंगे।

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया : इसलिए कि मैंने बार-बार कहा है कि मैं भारत के संविधान के संरक्षक सदन के अंदर बोल रहा हूं और मेरा पूरा अधिकार है ।

उपसभापति : मैं आपको बताऊं कि मैंने क्यों कहा आपने कहा कि "निकम्मी सरकार", आप इसे "निकम्मा" कहते हैं, मुझे कोई एतराज नहीं। मगर यह अल्फाज कि "यह कहता है", मैं समझती हूं कि यह अल्फाज "कहता है" इस सदन में कभी नहीं बोला जाता । "कहते हैं" भी बोल सकते हैं या "कह रहे हैं" मगर "यह कहता है" मेरे नजदीक फुटपाथ की जबान है, इस हाउस की नहीं है । मैं कभी नहीं बोलूंगी कि अहलुवालिया इस हाउस में यह बात कहता है । मैं आपसे यही कहूंगी कि आप यह बात कहते हैं । इसलिये मैंने कहा, बस ।

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया : महोदया,....

उपसभापति : बस बात खत्म हो गयी।

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया : आपने जो बात कही है मैं एक मल्टी लिंग्वुअल आदमी हूं । मैं बहुत भाषायें बोलता हूं । मैं बंगाली बोलता हूं, मैं पंजाबी बोलता हूं, मैं.... **(व्यवधान)**

उपसभापति : अफसोस की बात है कि मैं मल्टी लिंग्वुअल नहीं हूं । मैं सिर्फ एक भाषा बोलती हूं जो तमीज की भाषा है, बस।

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया : तो क्या मैं बदतमीज हूं

उपसभापति : मैं अपनी बात कर रही हूं । मैं आपकी बात नहीं कर रही हूं।

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया : महोदया, फिर आप इसमें.... **(व्यवधान)**

उपसभापति : मैं अपनी बात कर रही हूं, आप अपना भाषण करिये।

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया : अगर आप यही चाहते हैं कि मैं इस पर बहस पर बोलूं तो मैं बैठ जाता हूं.... (व्यवधान)

उपसभापति : आप बोलिये.... (व्यवधान) आप जरूर बोलिये।

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया : आप इसी तरह से अड़चनें डालेंगे और इस तरह.... (व्यवधान)

उपसभापति : देखिये, फिर समय निकल जायेगा, 5 मिनट हैं।

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया : एक सदस्य को बिखराव करने की कोशिश करेंगे तो यह गलत बात है।

उपसभापति : मैंने आपत्ति नहीं उठायी थी। आपत्ति हाउस के दो सदस्यों ने उठायी थी।

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया : आपत्ति उन्होंने उठायी थी "निकम्मी सरकार" पर।

श्री आरिफ मोहम्मद खान : जो आपने कहा माननीय उपसभापति जी...

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया : निकम्मी सरकार मानते हैं हम।

श्री आरिफ मोहम्मद खान : नहीं, निकम्मी सरकार पर आपको अधिकार है। आप किसी भाषा का प्रयोग करें मैं आपके अधिकारों पर किसी किस्म की रोक नहीं लगाना चाहता। वैसे आपने बिल्कुल सही कहा कि "वह कहता है" तो बिल्कुल मैं भी आपसे सहमत हूं। अहलुवालिया जी, आप सारी भाषायें बोलना जानते होंगे, लेकिन इस सदन में संसदीय भाषा बोलें, दूसरी भाषायें न बोलें।

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया : आप उस वक्त कहां थे जिस वक्त आपके प्रधान मंत्री ने, राजा विश्वनाथ प्रताप सिंह ने राजीव गांधी को कहा था—शट अप शट सिट डाउन। आप कहां थे उस वक्त? उस वक्त आपने शालीनता और सभ्यता अपने प्रधान मंत्री को क्यों नहीं सिखायी। बताइये।

उपसभापति : आप कश्मीर पर बोलिये, भाषा पर बाद में जिक्र करेंगे।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय : पार्टी, नीति की बात कर रहे हैं।

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया : लोक सभा की बात कर रहा हूं।

श्री आरिफ मोहम्मद खान : लोक सभा की भी बात न करें।

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया : अच्छा ठीक है।

उपसभापति : अपनी बात करिये, कश्मीर की बात करिये, समय नहीं है, आपका टाइम खत्म हो गया है।

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया : महोदया, टाईम तो अभी कहां, मैंने शुरू किया है।

उपसभापति : नहीं-नहीं, आधा घंटे से ज्यादा नहीं होगा, खत्म करें। लंच के बाद गुलाम नबी जी बोलेंगे।

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया : मैडम, कश्मीर में एक तरफ तो सिक्योरिटी एडवाइजर स्टेटमेंट देते हैं कि वहां के जितने भी जे०के०एल०एफ० वाईप आउट—कुरेशी – कुरेशी ने अपना स्टेटमेंट दिया कि ज०के०एल०एफ० का खात्मा कर दिया कि वहां पर अब कोई भी अलगाववादी ताकत नहीं है और दूसरी तरफ इस सदन में एक ऐसा बिल लाया जा रहा

है जो राईट टू लाइफ, राईट टू प्राइवेसी, राईट टू मूवमेंट राईट टू जजमेंट राईट टू फंडामेंटल राईट—सभी स्नेच कर रहा है। राईट टू एक्सप्रेशन हर चीज को छीनने की कोशिश कर रहा है। महोदया इन्होंने यू० एन० ओ० की बात की और यू० डी० ओ० अपने यूनिवर्सल डिक्लेयरेशन ऑफ ह्यूमन राईट पर कहता है—

"Right to life, liberty and security of persons. Freedom from slavery and servitude.

Freedom from torture or cruel inhuman and degrading treatment or punishment.

Right to recognition as a person before law.

Equal protection of law.

Right to effective judicial remedy.

Freedom from arbitrary arrest, detention or exile.

Right to a fair trial and public hearing by an independent and impartial tribunal.

Right to be presumed innocent until proved guilty.

Freedom from arbitrary interference with privacy, family, home and correspondence."

महोदया इन सारे अधिकारों को हनन करने के लिये यह बिल लाया गया और बिल में सीधे लिखते हैं:

"Any commissioned officer, warrant officer, non-commissioned officer or any other person of equivalent rank in the armed forces may, in a disturbed area,—

(a) if he is of opinion that is necessary so to do for the maintenance of public order, after giving such warning as he may consider necessary, fire upon or otherwise use force, even to the causing of death..."

यहां राईट टू लाईफ छीनी जा रही है। इसी तरह के काले कानून आगे भी बताये गये, पर मैं तो, महोदया, आपके माध्यम से इस मुल्क के प्रधान मंत्री राजा विश्वनाथ प्रताप सिंह को याद दिला देना चाहता हूं कि मैंने उन्हीं की भाषा का प्रयोग किया है मैंने अपनी कोई बात नहीं की है।

मैंने अपनी कोई बात नहीं कही है है क्योंकि आपके पास मौका नहीं है मेरी बात सुनने के लिए। मैंने तो उन्हीं की बात आपके सामने रखी है और यह विचार करने योग्य है कि क्या उनकी कथनी और करनी में कोई फ़र्क आ गया है?

इन्होंने पहले एक मुख्य मंत्री हटाकर, एक गवर्नर हटाकर जगमोहन को भेजा और जगमोहन के टाइम में जो कुछ वहां हुआ उसके बाद एक और गवर्नर भेजा और वह गवर्नर रो रहा है अकर लोगों से कह रहा है कि मैं क्या करूंगा? गवर्नर जगमोहन के जितने भी लोग यहां एडवाइजर बनकर आए थे, वही एडवाइजर हैं मैं कोई हैं। मैं कोई भी ऐक्शन लेना चाहता हूं कुछ भी करना चाहता हूं, वह रातों-रात खबर चली जाती है और वहां से निर्देश बदल दिए जाते हैं और दिल्ली से कंट्रोल किया जा रहा है महोदया, और तो और ये शांति की बात कहते हैं (व्यवधान)

THE DEPUTY CHAIRMAN: If the Members agree, then, we can dispense with the lunch hour and continue with the discussion.

SHRI S. S. AHLUWALIA: I will continue after lunch.

THE DEPUTY CHAIRMAN: But you have taken more than half-an-hour. I think that is enough.

SHRI S. S. AHLUWALIA: Madam, I need some more time.

THE DEPUTY CHAIRMAN: I am sorry. I know that you are making some points very well but the thing is that sometimes we have to stop even if anybody is making very good points. If the Members so agree, we will dispense with the lunch hour and continue with this important discussion.

SHRI S. S. AHLUWALIA: Madam, I can speak after lunch.

उपसभापति : आप तो कह सकते हैं, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। आपत्ति यह है कि हमें यह आज खत्म करना है। इसलिए अगर लंच-आवर डिस्पेंस करें तो अच्छा होगा।

We can continue and finish this.

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया : मैडम, लंच के बाद कंटीन्यू कर सकता हूँ।

उपसभापति : आधा घंटा हो गया, आपका बहुत टाइम हो गया। आई हैव गिवन यू एनफ़ टाइम। अब आप जल्दी जल्दी खत्म कीजिए।

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया : मुझे 10-15 मिनट और चाहिए।

THE DEPUTY CHAIRMAN: It is not possible.

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया : पासिबल है।

उपसभापति : अहलुवालिया जी, अब आप बैठ जाइए . . . । (व्यवधान) मैं यह हाउस आप ही का है। मेरी जेब से टाइम नहीं जा रहा है। इस हाउस पर लाखों रुपया खर्च हो रहा है। आप लंच आवर पर सस्पेंड करने को तैयार नहीं हैं और टाइम भी ज्यादा मांग रहे हैं। तो कहीं न कहीं तो आपको समझौता करना पड़ेगा अगर हम लंच आवर सस्पेंड कर दें तो मैं आपको 10-15 मिनट दे दूंगी।

You have to cooperate.

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI JAGDEEP DHANKHAR): Madam, let the lunch hour be suspended. It is a serious matter.

THE DEPUTY CHAIRMAN: I am requesting.

SHRI S. S. AHLUWALIA: No. Lunch hour we cannot suspend.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Then, you please conclude.

SHRI JAGDEEP DHANKHAR: I am sure the Leader of the Opposition will respond to the situation.

. . . (*Interruptions*) . . .

THE DEPUTY CHAIRMAN: There is a listed business. Mr. Jagesh Desai and other Members wanted to know when the discussion on Industrial Policy would be taken up. This is also important. It is listed at 4 o'clock. I do not know how we can finish the discussion on this before 4 o'clock . . . (*Interruptions*) . . . Yes, at 4 o'clock also we have short duration discussion on Sri Lanka. Now, how can I stretch the time?

SHRI JAGESH DESAI (Maharashtra): Please give ten minutes more ot Mr. Ahluwalia.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Then, we will have to dispense with the lunch hour.

SHRI VISHVJIT P. SINGH (Maharashtra): Let us curtail the lunch hour by ten minutes and allow Mr. Ahluwalia to complete.

THE DEPUTY CHAIRMAN: We cannot. It is a question of compromise. Actually his time is over. I gave him more than half-an-hour. So the time is over. If he wants

more time, then, I request the entire house to abide by the request of the Chair and dispense with the lunch hour.. (*Interruptions*) . But somebody else also has to speak. Why should anybody oblige only Mr. Ahluwalia and not other Members? Why not Mr. Ghulam Nabi Azad who is the next speaker?

SHRI JAGESH DESAI: It is for you to decide.

THE DEPUTY CHAIRMAN: It is not for me to decide. It is for the House to decide. I want the House to take a decision. ..(*Interruptions*) Then. I am adjourning the House for lunch and your speech is concluded

SHRI S. S. AHLUWALIA: No, Madam.

THE DEPUTY CHAIRMAN: We have to do something.

आपका टाइम खत्म हो गया है।

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया : इसमें मैंबर की बात नहीं है... (व्यवधान) इसके लिए क्या रूल है?

THE DEPUTY CHAIRMAN: I must tell you as to what is the rule. You are making a resolution. We allowed you. The total time allotted by the Business Advisory Committee was 4 hours, including the reply of the Minister and your speech Now we gave half an hour extra time to you. Now you either conclude so that I can call Mr. Ghulam Nabi Azad after lunch hour or we dispense with the lunch hour. I am putting these two proposals. You have already spoken for 14 minutes before.

इसलिए मैंने कहा कि आप 10 मिनट में खत्म कर दीजिए... (व्यवधान)

SHRI JAGDEEP DHANKHAR: Let the Leader of the Opposition accept the suggestion of dispensing with the lunch hour.

THE DEPUTY CHAIRMAN: I feel either you dispense with the lunch hour or you finish your speech. Why you want to be discriminating against Mr. Ghulam Nabi Azad?

SHRI S. S. AHLUWALIA: No, no, we are not discriminating.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Because he is the next speaker

SHRI S. S. AHLUWALIA: Yes, he will speak after me.

कुछ माननीय सदस्य : नहीं नहीं... (व्यवधान)

THE DEPUTY CHAIRMAN: I tell you, you took half an hour today and 14 minutes before. How much time you will take now?

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया : मैं पांच मिनट और लूंगा... (व्यवधान)

उपसभापति : चलिए आप बोलिए, लंच अबर नहीं करेंगे...

कुछ माननीय सदस्य : नहीं नहीं, लंच तो खाना ही है... (व्यवधान)

THE DEPUTY CHAIRMAN: I will not have the lunch hour today and let Mr. Ghulam Nabi Azad start his speech.

SHRI JAGESH DESAI: As I suggested, ten minutes of the lunch hour can be curtailed. ...(*Interruptions*).

THE DEPUTY CHAIRMAN: But why do you want to be nice only to one Member and not to others? Let us finish the work.

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया : मैं अपनी बात पांच मिनट में खत्म कर दूंगा... (व्यवधान) इसके बाद इनको बुलवाइए... (व्यवधान)

THE DEPUTY CHAIRMAN: Then I am adjourning the House and your speech is finished. (*Interruption*).

[The Deputy Chairman]

Now his speech is finished. I do not know what is so special about lunch today. I am not really objecting anybody not to eat lunch. I am also going to eat it. (*Interruptions*)... Mr. Jagesh Desai, then I will adjourn the House and Mr. Ahluwalia will speak for five minutes afterward and that will be finished. Let us come to some conclusion.

डा० अबरार अहमद खान : यह बहुत महत्वपूर्ण मसला है . . . (**व्यवधान**)

उपसभापति : आप मुझको सबक मत दीजिए। मैं इसकी महत्वपूर्णता को देखकर खाने का टाइम नहीं दे रही हूं ताकि इसको खत्म किया जा सके... (**व्यवधान**)

कुछ माननीय सदस्य : लंच का समय दीजिए . . . (**व्यवधान**)

THE DEPUTY CHAIRMAN: I am also saying the same thing. Now I will adjourn for lunch. After lunch, you speak for five minutes and finish.

The House is adjourned for lunch for one hour.

The House then adjourned for lunch at thirty-eight minutes past one of the clock.

The House reassembled after lunch at forty one minutes past two of the clock. **The Vice-Chairman (Shri Bhaskar Annaji Masodkar)** in the Chair.

SHRI SUBRAMANIAN SWAMY (Uttar Pradesh): Sir, the Cabinet Minister of Home Affairs is missing for the last 24 hours. I think he has resigned. Minister of State for Home Affairs is now supposed to reply. We are trying to find out where the Home Minister is.

SHRI V. NARAYANASAMY (Pondicherry): He went to Assam and Mr. Dinesh Goswami resigned. Wherever he goes, he makes Ministers to resign.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): Let us hear Mr. Ahluwalia.

SHRI SUBRAMANIAN SWAMY: Is the Home Minister going to say something about Bofors? I was told that he would make a statement on Mr. Devi Lal's stand on Commerce Minister, Mr. Arun Kumar Nehru.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR) : We are on Kashmir.

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया : उपसभाध्यक्ष महोदय, काश्मीर में अत्याचारों की कहानियां जितनी सुनाई जाय उतनी उतनी कम हैं और साथ-साथ अफ़सोस इस बात का भी हैं कि जो वहां इस तरह की घटनाएं घट रही हों, जब वहां के लोग अपने अधिकारों के बारे में मांग कर रहे हों, उस वक्त बिना किसी पावर के, आज तक मुझे पता नहीं कि सैनिक या अर्द्ध सैनिक बलों को ऐसा कोई प्रावधान दिया गया है, ऐसी कोई ताकत दी गई है वा नहीं कि बिना वारन्ट के या बिना कोई कोर्ट रिपोर्ट के, बिना कोई एफ़०आई आर० के किसी के घर में घुस कर उस पर अत्याचार करें, वहां की महिलाओं के साथ बलात्कार करें और उसकी कोई सुनवाई भी न हो। सारा काश्मीर उम्मीद बांधे दिल्ली की ओर देखता है और उमीद करता है कि हमारे साथ न्याय होगा। काश्मीर के बारे में बड़े-बड़े शायरों ने लिखा है—

गर फ़िरदौस बरमुये जमी अस्त,
हमी अस्तो, हमी अस्तो, हमी अस्तो,

अगर फ़िरदौस इस जमीन पर कहीं स्वर्ग है तो वह यहीं है, यहीं है, यहीं है और

उस जन्नत के बारे में आज लोग वहां कहते वहशी बनते जा रहे हैं और वह जन्नत दोजख के रूप में परिणित होती जा रही है और लोग परेशान हैं। हम कहते हैं कि लड़के पाकिस्तान क्यों मांग रहे हैं। लड़के पंजाब में ही इसी तरह से सैनिक और अर्द्ध सैनिक बलों के अत्याचारों से भाग गये। आज यहां से भाग कर उस तरफ़ जा रहे हैं और शरणापन्न होते हैं। कोई जंगल म भाग जाता है, कोई उस तरफ़ भाग जाता है। हम उन्हें रोक नहीं पा रहे हैं और हम रोकने की कोशिश भी नहीं कर रहे हैं। जो गांव आज तक हमारे साथ थे, जो गांव आज तक हिन्दुस्तान का नारा बुलन्द कर रहे थे, आज हम जबर दस्ती उनके दांत तोड़ रहे है, उनके कंठ रोक रहे हैं ताकि उनके मुंह से हिन्दुस्तान का एक शब्द भी निकलना बन्द हो जाय अफ़सोस इस बात का है कि हमने सारी पार्लियामेंट का किस तरह से मजाक उड़ाया है और यह सब कुछ कहने के साथ-साथ मैं यह भी कहना चाहूंगा कि जब गृह मंत्री को अच्छी तरह से पता था कि 22 जून को पार्लियामेंट बुलाने के लिये समन इश्यू हो गये और 7 अगस्त से पार्लियामेंट बैठने वाली है तो उसके बाद यह आर्डिनेंस पास कराने की क्या जरूरत थी, क्या हड़बड़ी थी ? हड़बड़ी यह थी कि ये घटनायें, ये अत्याचार पिछली अप्रैल और मार्च से होते जा रहे थे और बहुत सारी स्वयंसेवी संस्थायें वहां जाकर, घूमकर रिपोर्ट इकटठा कर रही थीं। इन्होंने यह आर्डिनेंस लाकर उन सारे अत्याचारों को जस्टिफ़ाई करने की कोशिश की है। 22 जून को एक तरफ़ समन इश्यू करते हैं कि संसद का अधिवेशन 7 अगस्त से शुरू होगा और दूसरी तरफ़ राष्ट्रपति के सिगनेचर के माध्यम से 5 जुलाई को यह आर्डिनेंस लागू किया जाता है जो मेरे ख्याल से....

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): Mr. Minister, he is making a very valid point that you have issued the Ordinance when the Session was already called. Please take note of it.

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया : महोदय अगर ऐसा हो और गृह मंत्री इतने सीरियस हों, गृह मंत्रालय इतना सीरियस हो तो शायद जो घटनायें कश्मीर में घट रही हैं वे न घटतीं। ये सीरियस नहीं हैं, तभी तो ये घटनायें घट रही हैं।....(व्यवधान).... मिनिस्टर आफ़ स्टेट तो सीरियस हैं, यह मुझे मालूम है।

उपसभाध्यक्ष (श्री भास्कर अन्नाजी मासोदकर) : अहलुवालिया जी, आप भी सीरियस हो जाइये।

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया : मैं तो सीरियस हूं, इसीलिये तो मैं कांस्टिट्यूशनल प्राबलम क्रियेट कर रहा हूं।

उपसभाध्यक्ष महोदय, वहां पर इस तरह की घटनायें घट रही हैं और जनता दल ने वहां पर अपना एक दफ्तर खोल दिया है। जिस जनता दल का नामोनिशान तक कश्मीर की घाटी में नहीं था; उस जनता दल के दफ्तर में क्या काम होता है ? वहां पर गवर्नर के दफ्तर से एक लिस्ट आती है कि किस किसको नेशनल सेक्यूरिटी ऐक्ट या टेरोरिस्ट डिटेंशन ऐक्ट में बंद किया गया है। यह लिस्ट वहां आती है और दूसरे ही दिन जनता दल के कार्यकर्ता उसके घर पहुंच जाते हैं और कहते हैं कि बताओ भाई तुम जनता दल की मेंबरशिप लोगे। तुम और तुम्हारा परिवार अगर यह करता है तो हम तुम्हारे आदमी को छोड़ने का आदेश निकालते हैं। वहां एक ग्रिवांसेज सेल बनाया गया है जो वहां के गवर्नर के अधीन काम करता है और उस सेल के माध्यम से जो जनता दल में अपना पूरा समर्थन देते हैं उनको छोड़ दिया जाता है। महोदय, आज वहां हालत यह है।....(व्यवधान)....है ही नहीं। इस तरह से

[श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया]

खोला जा रहा है और जबर्दस्ती बनाया जा रहा है। इसका इससे पहले वहां पर नामोनिशान तक नहीं था। यह जनता दल का रेक्रूटमेंट सेल है। उन्हें एक तरफ से तो टैरोरिस्ट डिटेंशन ऐक्ट में बंद किया जाता है और दूसरी तरफ उनसे मुचलका लिखाकर उनको छुड़ाया जाता है और इस तरह से उनको जबर्दस्ती मेंबर बनाया जा रहा है। महोदय, मैं जानना चाहता हूं सरकार ने वहां पर जिन लोगों को बंद किया है, एक तरफ तो वहां कुरैशी साहब बयान देते हैं कि जे.के.एल.एफ. का वहां खात्मा हो गया है और वहां पर किसी चीज की जरूरत नहीं है। अगर बिना ऐसे किसी बिल को पास किये आपने उनका खात्मा कर दिया है तो फिर वह स्पेशल पावर वहां की आर्म्ड फोर्सेज को क्यों दे रहे हैं? मेरा इस पर विरोध है। यही नहीं, महोदय, वहां पर Over 900 officials including 23 SPs and DSPs are reported to have sought either premature retirement or proceeded on long leave...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): Please conclude.

SHRI S. S. AHLUWALIA: These are valid points. I am concluding...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR). There are other speakers.

SHRI S. S. AHLUWALIA: I am concluding...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): I request you to conclude with this point.

SHRI S. S. AHLUWALIA: These are all very valid points. However, I am concluding just now. 900 आदमी आफिसर जो हैं वे क्यों छुट्टी पर जा रहे हैं और क्यों वे प्रीमेच्योर रिटायरमेंट मांग रहे हैं, यह मैं जानना चाहता हूं? उनको रोकने की जरूरत है या स्पेशल पावर देने की जरूरत है? मैं फिर राजा विश्वनाथ प्रताप सिंह के भाषण का हवाला देना चाहता हूं जो उन्होंने यहां पर कहा था। उस बात को मद्देनजर रखते हुए आप बिल पर फिर गौर फरमायें और सोचें कि आप क्या कहते हैं और क्या करते हैं। मैं यही कहकर अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं।

The question was proposed.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): Now, Mr. Ghulam Nabi Azad. We are taking up all these matters together, the Resolutions and the Bill. That is why I am calling another Member from the Congress (I) side.

श्री गुलाम नबी आजाद: माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, मुझे अफसोस है कि आज कश्मीर में यह स्पेशल पावर्स आर्म्ड फोर्सेज को देने की जरूरत पड़ी। सबसे पहले इसकी गहराई में जाना बहुत जरूरी है और यह देखना है कि बिल लाने की जरूरत क्यों पड़ी और इसके लिए कौन जिम्मेदार है। जब भी कश्मीर पर चर्चा होती है, तो सरकार की तरफ से एक ही बात सुनाई देती है जवाब में, कि कश्मीर की जो प्रोब्लम है यह पुरानी गवर्नमेंट से उन्होंने इनहेरिट की है। पिछले 8 महीनों में सदन के अन्दर और सदन के बाहर इस सरकार का एक ही जवाब कश्मीर के मसले के बारे में मिला है। हमारे जो भाई बहनें कश्मीर के बाहर रहते हैं उन्हें शायद यह ठीक लगता होगा कि कांग्रेस के शासन में या फारुख अब्दुल्ला के शासन में ही कश्मीर के हालात खराब हुए थे। लेकिन जम्मू-कश्मीर में जो लोग रहते हैं उनको यह यकीन दिलाना कि यह तबाही और बरबादी पिछली सरकार के दौर में हुई है। यह यकीन कोई भी उन्हें

नहीं दिला सकता । मेरे मित्र अहलूवालिया जी ने अपने भाषण में यह जिक्र किया कि अगर कश्मीर में यह हालत होती तो जनता दल की सरकार ने जहां अपने मेनीफेस्टो में हर वह चीज डाली है जो नामुमकिन भी थी या और पांच साल या दस साल के बाद होने वाली है तो कश्मीर समस्या को भी उन्होंने अपने मेनीफेस्टो में डाला होता । तो अगर कश्मीर में हालत गम्भीर होते तो इनके मेनीफेस्टो में इसके बारे में कोई चर्चा होती ? इनका मेनीफेस्टो कश्मीर के बारे में बिलकुल खामोश है । इसका मतलब यह है कि जिस वक्त इन्होंने सरकार सम्भाली थी उस वक्त कश्मीर के हालात बिलकुल ठीक थे इसलिए इसका जिक्र उन्होंने अपने मेनीफेस्टो में नहीं किया है। वहां तमाम डवलपमेंटल वर्क्स चल रहे थे, सड़क का, नहर का, बिजली प्रोजेक्टस का और नेशनल हाइडल प्रोजेक्टस का सब काम बराबर चल रहा था, जो आज बिलकुल ठप है । जियासत के तमाम एजूकेशनल इंस्टीटयूशंस चाहे कालेज हों या स्कूल हों या यूनीवर्सिटीज हों सब बराबर चल रहे थे । टेलीफोन तार यह तमाम चीजें चल रही थीं । शायद सितम्बर 89 के महीने में हमने उस वक्त एक पब्लिक मीटिंग की थी मुझे याद है कि रेडियो और टेलिविजन ने उसको कवर किया था । लेकिन आज रेडियो और टेलिविजन कहां हैं? आज कश्मीर की खबरें दिल्ली से या जम्मू से रिले की जाती हैं । वहां टेलीविजन सेंटर है लेकिन वहां कोई कामचारी नहीं है । आज रेडियो कश्मीर तो है, लेकिन रेडियो कश्मीर की खबरें कहां से रिले होती हैं दिल्ली और जम्मू से रिले होती हैं । रेडियो कश्मीर और दूरदर्शन भी कश्मीर से आज नहीं चलता है खाली वहां से न्यूज रिले होती है । इसी तरह से टूरिज्म का सवाल है । मेरे ख्याल में जितनी कामयाबी टूरिज्म ने सन 1987–88 और 1988–89 में हासल की उतनी पहले कभी नहीं की होगी । लेकिन इस साल शायद दो टूरिस्ट भी कश्मीर में नहीं जा पाए होंगे। अगर उस वक्त हालात खराब थे तो पिछले साल नवम्बर तक एक भी कश्मीरी को चाहे वह कश्मीरी पंडित हो या कश्मीरी मुसलमान हो, कश्मीर छोड़कर कश्मीर से बाहर क्यों नहीं निकला ।

इसी तरह से अगर काश्मीर में हालात खराब होते तो नेशनल कांफ्रेंस और कांग्रेस के शासन में लोग यू. एन. ओ. आफिस में जाते लेकिन पिछले साल नवम्बर तक एक भी आदमी यू. एन. ओ. के आफिस नहीं गया बल्कि उसके बाद दिसम्बर और जनवरी में न सिर्फ हजारों की संख्या में बल्कि लाखों की संख्या में लोग यू. एन. ओ. के आफिस में चले गये, न सिर्फ आम जनता बल्कि गवर्नमेंट इम्प्लायीज भी यू. एन. ओ. के आफिस में चले गये । इसका मतलब है कि नवम्बर तक केन्द्र में कांग्रेस की सरकार थी और जम्मू कश्मीर में कांग्रेस तथा नेशनल कांफ्रेंस की मिली-जुली सरकार थी । उस वक्त काश्मीर में हालात बिलकुल ठीक थे, टूरिज्म भी चलता था, डेवलपमेंटल वर्क्स भी चलते थे, रेडियो स्टेशंस भी चलते थे, टेलीफोन और तार भी चलते थे और वहां एजूकेशनल इंस्टीटशंस भी बराबर चलते थे । असली कारण जो काश्मीर में इन हालात के उत्पन्न होने का है । बदकिस्मती से सरकार उसके बारे में चुप है । जब भी काश्मीर के बारे में चर्चा हो तो यह सरकार अपने गिरेबान में झांक कर देखे । सबसे बड़ा कारण है कि केन्द्र में 1977 से भी ज्यादा एक कमजोर सरकार वजूद में आई है । यह सबसे बड़ा कारण है । इस कारण से न सिर्फ कश्मीरी मिलिटेंटस के हौसले बढ़े बल्कि मैं यह कहना चाहूंगा कि पाकिस्तान को भी यहां की कमजोर सरकार से बहुत बल मिला है । जब तक राजीव गांधी की सरकार केन्द्र में थी, बेनजीर भुट्टो या वहां के जनरल बेग जुर्रत नहीं कर सकते थे या जिस भाषा का उपयोग उन्होंने इस नयी सरकार आने के बाद किया वह भाषा वह पिछले साल तक नहीं प्रयोग करते थे । चाहे दबे लफ्जों में कुछ भी वे कहते थे लेकिन नेशनल लेबिल पर और इंटरनेशनल फोरमस में वे कभी भी अपनी बात का इस तरह से इजहार नहीं करते थे ।

[श्री गुलाम नबी आजाद]

दूसरा कारण है डिसाल्यूशन आफ असेम्बली। जिस वक्त असेम्बली भंग कर दी गयी उसी वक्त काश्मीर में डिस-इंटीग्रेशन का बीज बोया गया। उसका क्या कारण है? उसका मैं जवाब देना चाहता हूं। हमने शेख अब्दुल्ला साहब की पार्टी के साथ 1975 में एकार्ड किया। 22 साल शेख अब्दुल्ला जेल में रहे। वे कांग्रेस से हटकर अलग बात करते थे। लेकिन 22 साल के बाद इंदिरा गांधी जी की पोलिटिकल सूझबूझ से शेख मोहम्मद अब्दुल्ला अगर उनकी पार्टी नेशनल कांफ्रेंस मेन स्ट्रीम में आई। और उनके मरने के बाद फारुख अब्दुल्ला और कांग्रेस ने मिलकर सरकार बनाई। तो वे तमाम लाखों लोग जो 22 साल जेल में रहे थे शेख अब्दुल्ला के साथ कांग्रेस उनको मेन स्ट्रीम में लायी और उन्होंने अखण्ड भारत का नारा हमारे साथ, बाकी हिंदुस्तानियों के साथ और कांग्रेस के साथ लगाया। लेकिन जब असेम्बली भंग की गयी--अभी जिस असेम्बली के साढ़े तीन साल थे। तो काश्मीर के लोगों को यह महसूस हुआ कि क्योंकि केन्द्र में एक ऐसी सरकार बनी है जिसका सहयोग भारतीय जनता पार्टी कर रही है और यह भारतीय जनता पार्टी और जनता दल मिलकर काश्मीर के लोगों को प्रोटेक्शन नहीं दे सकते हैं क्योंकि कश्मीर के बारे में और विशेष रूप से आर्टिकल 370 के बारे में भारतीय जनता पार्टी का एक अपना व्यू 1947 से रहा है, इसलिए वे समझ रहे थे कि बी. जे. पी. की मदद से जो सरकार चल रही है वह यकीनन बी. जे. पी. के इशारों पर चलेगी और हमारे हित की रक्षा नहीं कर सकती है। यह दूसरा कारण था वहां के हालात खराब होने का।

तीसरा कारण था लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की मदद न लेना। मैंने पिछली दफा भी जब काश्मीर के बारे में यहां चर्चा हुई थी तो कहा था मेरे ख्याल में काश्मीरी

3.00 P.M. मुकाबलतन बहुत शरीफ आदमी हैं।

उपसभाध्यक्ष जी, मैं बताना चाहता हूं कि हिंदुस्तान के किसी भी कोने में, चाहे कितने ही लोग वहां के सेक्यूलर हों, चाहे कितने ही नेशनलिस्ट हों, लेकिन आप अगर एस. पी. से लेकर डाइरेक्टर जनरल, पुलिस तक और डी. एस. पी. से लेकर डाइरेक्टर जनरल, पुलिस तक और नीचे आफिसर से लेकर ऊपर आफिसर दूसरी स्टेट से लायेंगे, तो कोई भी लोकल आफिसर आपकी मदद नहीं करेगा।

यह चाहे आप कश्मीर को छोड़कर किसी भी दूसरे प्रांत में देखिये, चाहे उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में या तमिल नाडू में देखिये, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर की स्टेट है, जहां का गवर्नर बाहर का, जहां गवर्नर के एडवाइजर्ज बाहर के, जहां चीफ सेक्रेटरी बिहार के, जहां पांच डाइरेक्टर जनरल बाहर के हैं, जहां इंसपेक्टर जनरल, पुलिस बाहर के हैं, जहां डी. आई. जी. बाहर के हैं, जहां एस० पी० बाहर के हैं, जहां सेक्रेटीज बाहर के हैं--मेरे ख्याल में आपने उन पर विश्वास नहीं रखा है।

तो आप उनसे क्या उम्मीद करते हैं? वह कैसे आपकी मदद करें। ताली दो हाथों से बजती है। मैं आपको बहुत पीछे 1947 में ले जाना चाहता हूं। 1947 में कबायलियों ने कश्मीर पर हमला किया था। तो उनको किसने पकड़ा था? उनको कश्मीर की पुलिस ने पकड़ा था।

1965 में पाकिस्तान ने कश्मीर पर हमला किया। उनको किसने पकड़ा था? कश्मीर की पुलिस और कश्मीर के लोगों ने पकड़ा था। 1971 में पाकिस्तान ने कश्मीर पर हमला किया। कश्मीर के लोगों ने और कश्मीर की पुलिस ने पकड़ा था। लेकिन उस वक्त अंतर इतना था कि हमने कश्मीर की लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को विश्वास दिया था।

हमने अपना तमाम नेशनल इंटरेस्ट उनके हाथों में दिया था, अपनी इज्जत उनके

हाथ में दी थी कि आप हिंदुस्तान की एकता और अखंडता को अगर बचाना चाहते हैं, तो आप कुछ करके दिखाइये, लेकिन आज हमने उन पर विश्वास नहीं किया है, उसने उन पर भरोसा नहीं किया है।

हम यहां दिल्ली से, रिमोट कंट्रोल से कश्मीर को काबू करना चाहते हैं। माफ कीजिए, रिमोट कंट्रोल से कोई भी स्टेट और विशेष रूप से जम्मू व कश्मीर जैसी सेंसिटिव स्टेट तो नहीं चल सकती है।

चौथा कारण मैं बताना चाहता हूं कि वहां की पोलिटिकल पार्टी, आम जनता की तो मैं बात ही नहीं करता, लेकिन पोलिटिकल पार्टीज, जिनमें कांग्रेस, जिसका 105 साल का इतिहास है, नेशनल कान्फ्रेंस जिसकी अपनी तारीख है, अपनी एक हिस्ट्री है, इतिहास है कश्मीर में, मुझे आज तक बताइये, आठ महीने हुए, इन आठ महीनों में आपने अगर किसी से बात की हो इधर से सरकार की तरफ से चाहे केंद्रीय सरकार हो चाहे वहां पहले के गवर्नर ने जो हमारे बहुत बुजुर्ग साथी हैं, हमारे बहुत ही अच्छे ताल्लुकात हैं, हमारे ख्याल में पंद्रह साल से गवर्नर जगमोहन यहां बैठे हैं। आठ महीनों में न पहले गवर्नर ने और न आज के गवर्नर ने किसी पोलिटिकल पार्टी से एक दफा बात नहीं की है।

वहां मुख्य मंत्री था, जिसको इस सरकार ने डिसमिस किया। उस मुख्य मंत्री से, आज तक बात नहीं की गई थी। सिर्फ एक बार पिछले दिनों जब इस सरकार को लगा कि हालात बहुत खराब हैं। लेकिन मैं पूछता हूं कि क्या वहां के पिछले गवर्नर ने या आज के गवर्नर ने एक दफा भी बात की है? वहां मंत्रिमंडल था। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या किसी ने एक दफा भी उस मंत्रिमंडल से बात की?

वहां कांग्रेस की पी०सी०सी० के प्रेजीडेंट थे और बाकी आफिस बेयरर्ज वहां से कांग्रेस के एम० पी० इस सदन में और दूसरे सदन में हैं। उदाहरण के लिए एक दफा भी मुझे बताइये कि किसी लोक सभा या राज्य सभा के एम०पी० से बात की हो?

मैं कहता हूं कि वहां दूसरी पालिटिकल पार्टीज हैं, वहां सोशल आर्गेनाइजेशंस है। मैं पूछना चाहता हूं कि किसने और कब वहां की किसी पोलिटिकल पार्टी से किसी सोशल आर्गेनाइजेशन से या किसी दूसरी आर्गनाइजेशन से बात की है।

क्या ऐसे किसी स्टेट का मसला हल हो सकता है कि आप वहां किसी से बात ही नहीं करें। यह दूसरा कारण है जब वहां की एडमिनिस्ट्रेशन को आपने नजरअंदाज कर दिया, वहां की पोलिटिकल पार्टीज को, एस्टेब्लिश्ड पोलिटिकल पार्टीज को, जिसकी दो-तिहाई, तीन-चौथाई मेजारटी हाउस में थी, उनसे बात नहीं की, तो कश्मीर का, जाहिर है कि मसला बिगड़ेगा ही, हल नहीं होगा।

पांचवां कारण को आर्डीनेशन है। सैंटर और स्टेट में कोई कोआर्डीनेशन नहीं है, कोई नीति नहीं है, कोई पालिसी नहीं है। डे टू डे पालिसी है, पेच वर्क है। यह भी एक बड़ा कारण है। छठा बताना चाहता हूं जो विचार धारा जम्मू-काश्मीर के बारे में इस सरकार की है, जो पर्सपक्टिव है वह डिफरेंट हैं। बी०जे०पी० के सोचने का अलग तरीका है, सी०पी०एम० के सोचने का अलग तरीका है और जनता दल के सोचने का अलग तरीका है।... (व्यवधान) लेकिन जिस केन्द्रीय सरकार का, जहां पोलिटिकल पार्टीज का डिफरेंट परसप्शन हो सोचने का। वहां काश्मीर, आसाम और पंजाब जसे गंभीर मसले हल नहीं हो सकते हैं। इसलिए इस सरकार में एक गंभीरता की जरूरत है कि यह अपनी विचारधारा को एक करे। इस सरकार में सब से बड़ा इन-फाइटिंग का मसला है। इस सरकार में तो हर दूसरे दिन कोई न कोई एक्सीडेंट होता है। मेरे ख्याल में पिछले 8 महीनों में इस सरकार के दर्जनों एक्सीडेंट हुए हैं और तीन दफा यह सरकार इंटेंसिव केयर में चली गई। हमने सुना है कि लोग छोड़ कर भाग जाते हैं। मर्द किसी पत्नी की पिटाई करता है तो वह मायके चली जाती है, लेकिन मर्द भाग जाए तो यह

[श्री गुलाम नबी आजाद]

तो नामर्दी है। इससे कोई बड़ी बात नहीं हो सकती कि प्रधान मंत्री ही खुद छोड़ कर चले गए, मंत्री तो हमने भागते देखे हैं लेकिन जिस देश का प्रधान मंत्री ही भाग जाए तो यह नामर्दी की बात है। यह मर्द की बात नहीं हो सकती। .... (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया : **

श्रीमती कमला सिन्हा (बिहार) : उपसभाध्यक्ष महोदय, अहलुवालिया जी के इस रिमार्क का एक्सपंज करवाया जाए।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): They are not going on record.

सभा में कुछ मजाक भी चलता है। अभी बैठिए।

श्री गुलाम नबी आजाद : माननीय उपसभाध्यक्ष जी, मेरे कहने का मतलब था कि इस सरकार का सारा समय अपनी लड़ाइयों में, अन्दरूनी लड़ाइयों में निकल जाता है। इसे सोचने का समय ही नहीं मिलता, काश्मीर, पंजाब और आसाम के बारे में यहां रोज स्टेटमेंट देने से सरकार नहीं चलती है। यह तो फिर स्टेटमेंट सरकार हो गई। एक स्टेटमेंट सुबह आती है, एक स्टेटमेंट शाम को आती है और एक स्टेटमेंट दोपहर को आती है। मनिफस्टो पढ़कर एक स्टेटमेंट दे दो। अगर उससे हिन्दुस्तान की सरकार चल सकती है और अगर उससे काश्मीर, पंजाब और आसाम के मसले हल हो सकते तो मेरे ख्याल में कांग्रेस की सरकार तो दिन में 24 स्टेटमेंट देती। इसलिए इस स्टेटमेंट सरकार से काश्मीर जैसा मसला हल होने वाला नहीं है। इस आपस की लड़ाई से मसला हल होने वाला नहीं है।

Not recorded.

माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहता हूं कि यह सरकार कितनी अनसटन है मेरे ख्याल में जहां तक मुझे जानकारी है 1947 से ले करके आज जब भी 15 अगस्त को लाल किले से झंडा फहराया जाता था तो डिफेंस मिनिस्टरी अपने कार्ड में लिखती थी कि फलां-फलां प्रधान मंत्री, चाहे वह इंदिरा गांधी हो, राजीव गांधी हो, मोरारजी देसाई हो, फलां टाईम से 7 बजे फ्लैग होस्टिंग करेंगे। लेकिन उपसभाध्यक्ष जी, आपको आश्चर्य होगा कि इस दफा हिन्दुस्तान के इतिहास में डिफेंस मिनिस्टरी को भी मालूम नहीं था कि 15 अगस्त तक यही प्रधान मंत्री होगा या दूसरा प्रधान मंत्री होगा, क्योंकि अपने कार्ड में प्रधान मंत्री का नाम नहीं लिखा था। खाली लिखा था :

The Prime Minister of India will unfurl the National Flag at 10 minutes past 7.

तो इसका मतलब है कि जिस देश की डिफेंस मिनिस्ट्री को यह यकीन नहीं होगा कि एक हफ्ते के बाद हिन्दुस्तान का कौन प्राइम मिनिस्टर हो सकता है, आप उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां कौनसी नीति चल सकती है, कौनसा प्रोग्राम चल सकता है, कौनसी पालिसी चल सकती है।

माननीय उपाध्यक्ष जी काश्मीर समस्या का सबसे बड़ा कारण यह है कि एक डिवाइडेड हाउस है, डिवाइडेड पार्टियों की है यह गवर्नमेंट और जहां इस तरह के हालात हों--कोई भी बाहर की ताकत हो या अंदरूनी ताकत हो, उसको सीरियसली नहीं ले सकती। जहां गवर्नर की एक नीति हो, परस्पेक्टिव हो और जहां होम मिनिस्टर का दूसरा परस्पेक्टिव हो, काश्मीर अफेयर्स को देखने वाला मंत्री हो--उसका दूसरा परस्पेक्टिव हो और जहां कि प्रधान मंत्री का कोई परस्पेक्टिव हो न हो तो ऐसे हालात से यह सरकार ऐसी समस्याओं से कैसे निपट सकती है?

माननीय उपाध्यक्ष जी, यहां एक फारसी का शेर मैं कहना चाहूंगा . . . (व्यवधान) . . .

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): Mr. Azad, please conclude. You have already taken twenty minutes.

SHRI GHULAM NABI AZAD: I have taken twenty minutes. But do you want me to talk about Kashmir, or, it is only a question of formality? If it is only a formality, it is all right. I think I can take some time from my colleagues. I know about Kashmir

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): If your other colleagues agree, no problem.

श्री गुलाम नबी आजाद : पुराने जमाने में एक बादशाह की हुकूमत थी और उस बादशाह के डिफरेंट सोच वाले राजे-महाराजे और नवाब वगैरह थे। तो एक फारसी के शायर ने उस सरकार के बारे में कहा था, वह मैं पढ़ देता हूं। हमारे सत्ता पक्ष के लोग, उसे अपने ऊपर न लें, लेकिन उस वक्त के एक शायर ने उस बादशाह की सरकार के बारे में क्या कहा था, वह मैं कहना चाहता हूं—

"गुर बिशाहो, सग वजीरे,
मोश दीवान, मे शबद।
ईचनीन गर अरकाने हुकूमतस्त,
मुल्क वैरान मे शबद ।।"

गुर बिशाहो-बिल्ली अगर बादशाह हो। मैंने पहले कहा कि आप अपने पर न लें। मैं किसी बादशाह के जमाने का जिक्र कर रहा हूं। गुर बिशाहो-बिल्ली अगर बादशाह हो। सग वजीरे—कुत्ता अगर मिनिस्टर हो। मोश दीवान—चूहा अगर दीवान हो। ईचनीन गर अरकाने हुकूमतस्त—अगर ये सब मिलकर हुकूमत के, सरकार के कांस्टीट्यूएन्ट्स हों तो वह देश वीरान हो जाएगा।

गृह मंत्रालय मे राज्य मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय) : इन पावर्स के देने से नुकसान क्या है, उसपर बोलिए ?

श्री कैलाश नारायण सारंग (मध्य प्रदेश) : महोदय, एक शायर ने कहा है . . . (व्यवधान) . . .

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया : बैठ जाओ।

. . . (व्यवधान) . . .

श्री कैलाश नारायण सारंग : "रोने-धोने से मुकद्दर बदलने से रहा, गीली पलकों ये हंसी ख्वाब सजाते क्यों हो।"

श्री गुलाम नबी आजाद : माननीय उपाध्यक्ष जी, जो आज के हालात हैं, उसके लिए जो सबसे बड़ा कारण है, वह है वहां की डायरेक्शनलैस सैक्युरिटी फोर्सेस। महोदय, मुझे पूरा आदर है इस देश की आर्म्ड फोर्सेस का, सी०आर०पी० का, बी० एस०एफ० का। मुझे कुछ महीने होम मिनिस्टरी में रहने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैंने उनके साथ काम किया है। मुझे पूरा आदर है, उनके प्रति और आज इस देश की 80 करोड़ जनता आभारी है देश की सेक्यूरिटी फोर्सेस की कि वह अपनी जान की बाजी लगाकर, अपनी जान पर खेलकर हमारे देश की रक्षा करते हैं।

DR. G. VIJAYA MOHAN REDDY: Do you agree with what all Mr. Ahluwalia has said?

SHRI GHULAM NABI AZAD: I am coming to that. लेकिन उसके लिए एक ताकतवर घोड़े की जरूरत होती है। जब घोड़ा मजबूत हो तो उसकी पीठ पर एक ताकतवर घोड़ा-सवार होना चाहिए, जो लगाम अपने हाथ में लें। लेकिन जब घोड़े पर आप किसी बिल्ली या चूहे को बैठा देंगे तो घोड़ा फेंक मारता है। यही आज हालत हमारे जम्मू-कश्मीर में है। आर्मी के बारे में

[श्री गुलाम नबी आजाद]

हमें आदर है, हमें रेस्पेक्ट है, वे हमारे प्रोटेक्टर हैं, लेकिन कश्मीर में, दुर्भाग्य से हमारे डिफेन्स मिनिस्टर भी प्रधानमंत्री जी हैं, मैं बड़े आदर से उनका नाम लेता हूं, लेकिन वह घोड़ा-सवार नहीं है, उनका वजन बहुत हल्का है और घोड़ा बहुत भारी है, इसलिए उनकी कुछ चलती नहीं है। आज मैं बहलुवालिया जी से पूरा सहमत हूं, उन्होंने जो कहा है। उन्होंने मेरे ख्याल में जो कहा है, वह सौ का सिर्फ एक हिस्सा है। 99 परसेंट उन्होंने नहीं कहा है क्योंकि इस सदन के घंटों और मिनटों में वह पूरी रिपोर्ट नहीं आ सकती, उसके लिए महीने चाहिए। आज सिक्योरिटी फोर्सेज ने कश्मीर में जो किया मैं सब सिक्योरिटी फोर्सेज का नाम नहीं लेता, उनमें बहुत अच्छे आदमी भी हैं, लेकिन चंद इंसानों ने ऐसा किया। हिन्दुस्तान की आर्मी का विश्वास, विशेष रूप से मैं कहना चाहूंगा कि जब भी हिंदुस्तान में राइटस होते थे और अगर लोकल पुलिस किसी की साईड लेती थी तो इस देश की माइनोरिटी सबसे पहले कहती थी कि आर्मी को बुलाओ, मेजोरिटी वालों ने कभी मांग नहीं की आर्मी को बुलाने के लिए, हमेशा माइनोरिटी ने की है क्योंकि माइनोरिटी को उन पर विश्वास था, लेकिन आज चंद सिपाहियों ने उस 45 साल की इंडिपेंडेंट भारत की आर्मी पर एक काला धब्बा लगाया है, जो शायद आने वाले कई वर्षों तक मिट नहीं सकता। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? इसके लिए जिम्मेदार है इस देश का डिफेन्स मिनिस्टर, जो इस देश का प्रधानमंत्री भी है। डिफन्स में क्या हो रहा है, अगर इसके लिए उनके पास टाईम नहीं है तो डिफेन्स किसी दूसरे मंत्री को दे दें। अगर उनके पास टाईम नहीं है तो किसी डाक्टर ने नहीं कहा है कि आप डिफेन्स मिनिस्टरी अपने पास रखो।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं बतलाना चाहता हूं कि आज जो कश्मीर की औरतों के साथ हुआ, चाहे कहीं की भी हों, यह कश्मीर का ही सवाल नहीं है, अगर तमिलनाडु में भी होता तो मैं इसी तरह से बोलता, इसी जोर से बोलता क्योंकि औरतों का कोई धर्म जात नहीं होता, औरतें मांएं होती हैं, चाहे वे कश्मीर की हों, चाहे बंगाल की हों, चाहे आसाम की हों, औरत औरत है और उसने हम सबको जन्म दिया है। उस औरत के साथ कश्मीर में क्या हो रहा है, शायद वह नाजियों ने भी नहीं किया, डिक्टेटर्स ने भी नहीं किया मेरे भाई शायद मेरठ का, बिहार का, भागलपुर का नाम लगे, हमें शर्म है, मैंने पिछली मीटिंग में भी कहा, अफसोस है भागलपुर के लिए भी, हमें शर्म है मेरठ के अत्याचार पर भी, लेकिन मैं उस मौत को अच्छी मौत कहूंगा, बजाय जो बेइज्जती की मौत होती है। जो मौत गोली से हो जाय, वह मौत जलालत की मौत से कई गुना अच्छी होती है। आज जो इबरतनाक बातें कश्मीर में हो रही हैं, वह दस दफ़ा मरते हैं, दस दफ़ा जीते हैं, वह सौ दफ़ा मरते हैं, सौ दफ़ा जीते हैं। मैं कहूंगा डिफेन्स मिनिस्टर साहब से, अगर इसी तरह से आपको उन कश्मीरियों के साथ अत्याचार करना है तो आप सबको एक लाईन में लगाकर गोली मार दीजिए, उन सबको पानी में जहर मिलाकर पिला दीजिए। दस साल की लड़कियों के साथ रेप, 12 साल की लड़कियों के साथ रेप यह 87 पन्नों की रिपोर्ट मेरे पास है, जिसके दो-चार पन्ने मैंने यहां पढ़े हैं। हमने पहले ऐसा नहीं सुना था, हमने नहीं सुना था कि एक सिपाही ने मां और बेटी के साथ रेप किया हो। यह हिंदुस्तान की सभ्यता नहीं है, यह इंसान की सभ्यता नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं, जो टेररिस्ट हैं, उनके बारे में हमारी भी उतनी ही भावनाएं हैं, जितनी सिक्योरिटी फोर्सेज की। हर हिंदुस्तानी आतंकवादियों के खिलाफ है, हर हिंदुस्तानी टेररिस्ट के खिलाफ़ है क्योंकि उन्होंने हमारे देश की एकता और अखंडता को चेलेन्ज किया है। यह माना कि वह

पाकिस्तान का प्रचार करते हैं, लेकिन अध्यक्ष जी, मैं बताऊंगा वहां के टेररिस्ट 20 साल भी अभी आने वाले वक्त में कश्मीरी लोगों को पाकिस्तान के प्रति कन्विस करने में असफल होते जबकि हमारी कुछ फार्सेस ने पिछले आठ महीनों में उन्हें पाकिस्तान बनाने के लिए कोन्स किया है। मैं एक आदमी का नाम लेना चाहूंगा। जब आर्म्ड फोर्सिस ने उसकी लड़की के साथ, उसकी पत्नी के साथ रेप किया और उसको लटकाकर रखा 3 दिन पेड़ के साथ तो जब वह वापिस आया तो उसने कहा कि मुझे आज तक यह मालूम नहीं होता था कि यह लोग आजादी क्यों मांग रहे हैं? "सब लोग आजाद, आजादी कहते थे तो मैं भी कहता था कि आजादी दो लेकिन मुझे मालूम नहीं था परन्तु आज पहली दफा मुझे मालूम हुआ कि क्या आजादी हम चाहते थे।" तो इसका मतलब है कि हमारी वह फोर्सिस उन टेररिस्ट को, उन मिलिटेंटस को मदद कर रही हैं, वह हिन्दुस्तान की मदद नहीं कर रही है, वह पाकिस्तान बनाने में उनकी सहायता कर रही है कि तुम अगर 2 हो पाकिस्तानी हो तो 10 हो जाओ, अगर 10 हो तो 30 हो जाओ। मैं यह कहूंगा कि इसका सारा इल्जाम देश के प्रधान मंत्री और डिफेंस मिनिस्टर पर है। अगर वाल कश्मीर को कुछ हो गया, अगर वह अलग हो गया तो मैं टेररिस्ट पर तो इल्जाम लगाऊंगा ही लेकिन इसकी सब से बड़ी जिम्मेदारी सरकार की और देश के प्रधान मंत्री की है। ... (व्यवधान)...

SHRI T. A. MOHAMMED SAQHY (Tamil Nadu): It is a legacy of the past.

SHRI GHULAM NABI AZAD: You can have your say when you speak.

SHRI VITHALBHAI M. PATEL (Gujarat): You don't take it seriously.

उपाध्यक्ष (श्री भास्कर अन्नाजी मासोदकर) : आपको कितना टाइम चाहिए?

श्री गुलाम नबी आजाद : जस्ट फाइव मिनट।... (व्यवधान)...

श्री बृजलाल शर्मा (हिमाचल प्रदेश) : कश्मीर के अलग होने की संभावना लगती है आपको?

श्री गुलाम नबी आजाद : माननीय अध्यक्ष जी, पंजाब में भी टेररिस्ट ने यही कोशिश की थी कि हिन्दू और सिख के बीच में लड़ाई हो जाए ताकि उनका काम आसान हो जाए, लेकिन उस वक्त की सरकार ने और कांग्रेस पार्टी ने जो प्रोग्राम पंजाब में किया, कई सैकड़ों, हजारों पब्लिक मीटिंग्स हमने पंजाब में की और वहां के हिन्दू और सिखों को एक करने की कोशिश की और जो सिख टेररिस्ट की मंशा थी कि हिन्दू और सिख फसादात हों तो उनका मसला हल हो जाता, वह हमने नहीं होने दिया। इसी तरह से कश्मीर में कश्मीर के मुस्लिम टेररिस्ट चाहते हैं कि यह लड़ाई टेररिस्ट और सिक्युरिटी फोर्सिस की न बने, यह लड़ाई कश्मीर आवाम के और सिक्युरिटी फोर्सिस की बने, मुझे अफसोस है कि यह सरकार उस फंदे में फंस गई है। जो टेररिस्ट चाहते थे कश्मीर के, वह इस सरकार ने पूरा किया। वहां के गरीब लोगों को, जो टेररिस्ट नहीं थे, उनको भी फंसाकर उनकी मंशा इस सरकार ने पूरी की।

मुझे एक आर्मी आफिसर की बात याद आती है। उन्होंने कहा कि हम इसलिए सबको पकड़ते हैं--औरतों को भी, बच्चों को भी, लड़कों को भी, कि हम सब गांव के गांव की पिटाई करें, जो चोर होगा वह कहेगा कि हम चोर हैं। अगर यह इंटेलिजेंस सिक्युरिटी फोर्सिस की है, माननीय अध्यक्ष जी, मेरे 5 पार्लियामेंट के साथियों को हथियार दीजिए, हम भी पूरी दिल्ली की पिटाई करेंगे और कहेंगे कि कोई न कोई चोर होगा। यह कौन सी इंटेलिजेंसी है,

[श्री गुलाम नबी आजाद]

कौन सी बहादुरी है कि निरअपराध आदमियों पर, जिसके हाथ में कुछ भी नहीं है, आप उसको पीटो और कहो कि पांच हजार में से एक न एक सबको जब पीटेंगे तो एक न एक नाम लेगा ही ! यह तो नामर्दी की निशानी है। यह इनएफीशेंसी की एक्सट्रीम हालत है। यह पालिटीकल बैंकरप्टी और इनएफीशेंसी की लास्ट स्टेज है। अगर यह हमारी सिक्युरिटी फोर्सेज का हाल है तो हमें बहुत अफसोस है उस पर। माननीय उपसभाध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी से अब कुछ क्लेरिफिकेशंस चाहूंगा। बदकिस्मती तो यह है कि न तो प्रधान मंत्री जी सीरियस हैं, न होम मिनिस्टर सीरियस हैं। मैं भी 6-7 साल मिनिस्टर रहा... (व्यवधान)

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): This House is very serious.

श्री गुलाम नबी आजाद: कागज और फाइल हमारे हाथ में होता था और हमारे आज के मंत्री जी तो जैसे सिनेमा देख रहे हैं टिप्पणियां करके। मैंने पिछली दफा भी देखा, आज भी देखा। महोदय, अगर आप इनका पेपर उठाकर देखें तो अगर दो शब्द उन्होंने लिखे होंगे तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। आसान नहीं, यह ऐसे मामले हैं जिनका आपको जवाब देना होगा।

But they are not interested. I wonder why they have come here and why they have become Ministers. They are least interested and their answers are good-for-nothing.

श्री सुबोध कान्त सहाय: खूबसूरत चेहरा है, कभी-कभी देखने को मिलता है, देखने दीजिये।

श्री गुलाम नबी आजाद: लिख भी नहीं सकते हैं। यहां सिनेमा देखने के लिये मत आइये आप।

श्री सुबोध कान्त सहाय: चालीस साल तक सिनेमा आपने देखा है ... (व्यवधान) अगर है तो जिगर थाम कर बैठो, जवाब देंगे। You do not have a right... (*Interruptions*).

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): Please sit down. Let him conclude. (*Interruptions*).

SHRI V. NARAYANASAMY: In eight months you have completely spoiled the atmosphere..

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): It is a very serious matter. Let us not interrupt. (*Interruptions*).

श्री गुलाम नबी आजाद: माननीय उपसभाध्यक्ष जी, मैं आखिर में सिक्योरिटी फोर्सेज के अत्याचार के बारे में कुछ कोट करना चाहूंगा ... (व्यवधान) ... अच्छा जब मैं जवाब सुनूंगा तभी पता चलेगा कि उन्होंने कुछ देखा है।

मान्यवर, अब यह परसों--

"The Jammu and Kashmir Director-General of Police, J. N. Saxena, said here today that 32 cases of excesses by security forces were being investigated and, in one such case after the investigation, 12 officers have already been put under suspension."

यह सिक्योरिटी फोर्सेज क्या यह तो लोकल पुलिस की बात करते हैं। मैं पहला सवाल पूछना चाहूंगा माननीय मंत्री जी से कि परसों का हिन्दुस्तान टाइम्स का सैंटर पेज पढ़िये, जिसमें उन्होंने कहा है कि 32 पुलिस आफिसर्स के खिलाफ हमने

केस रजिस्टर्ड किये हैं, 12 को सस्पेंड कर दिया है। यह तो पुलिस का काम है। मैं आर्मी के बारे में पूछता हूं जो डी०जी०पी० के अन्तर्गत नहीं हैं और जिसे आप प्रधान मंत्री जी से पूछकर बता सकता हैं कि जिन लोगों ने यह रेप्स किये हैं मेरे ख्याल से उनकी संख्या 100 से ऊपर है, इनमें डिफेंस मिनिस्ट्री ने या डिफेंस मिनिस्टर ने कौन सा एक्शन लिया है? कितनों को सस्पेंड किया है? कितनों को डिस्मिस किया है?
This is a very specific question.

दूसरा, मैं पूछता हूं कि जो मायग्रेंट्स हैं कश्मीर से आये हुये हमारे दूसरे हिंदू भाई। जब वे नये-नये आये थे तो जब पॉलिटिकली आपने उनको एक्सप्लाइट करना था तो कंधों पर चढ़ाकर पूरे हिंदुस्तान में नचाते थे उनको, कांग्रेस को बदनाम करने के लिये। लेकिन एक दफा उनको नचाकर, कांग्रेस को बदनाम करके अब उसके बाद उनको कुएं में फेंक दिया। उनकी क्या हालत है? उनकी आज व्यवस्था क्या है. उनके लिये आप क्या कर रहे हैं: वह दर-दर भटक रहे हैं।

श्री सिकन्दर बख्त (मध्य प्रदेश) : कम से कम उनके लिये नाचना शब्द तो न कहें।

श्री गुलाम नबी आजाद : मुझे माफ कीजिये, मैंने बी०जे०पी० नहीं कहा था। बी०जे०पी० ने ही नचाया था। अब मैंने आदर रखा था तो आप कहलवाना चाहते हैं तो मैं कह दूं कि किसने नचाया था। बी०जे०पी० ने ही नचाया था तो उनके लिये आप क्या करना चाहते हैं?

तीसरा सवाल है--क्या इस गवर्नमेंट ने कश्मीर के प्रति कोई पॉलिसी बनायी है। इस वक्त चार टाप मिलिटेंट्स दिल्ली में सरकार ने बुलाये हैं, एक दूसरे बहाने से किसी का दिल का ईलाज करने के लिए। मेरी इल्तजा है कि वह दिल और टांग का इलाज कम कराने के लिए और उनसे बातें करने के लिए बुलाया है। तो मैं होम मिनिस्टर से पूछना चाहता हूं कि यह बातचीत किससे हुई और बात कहां तक पहुंची है?

महोदय, तीसरा सवाल यह है कि फारूख अब्दुल्ला को पहले तो डिसमिस करके भगा दिया और अब देश में वापस ला रहे हैं, टेलीफोन पर टेलीफोन कर रहे हैं कि वापस आओ। हमें तो मालूम नहीं लेकिन अखबारों में हमने पढ़ा कि प्रधानमंत्री जी ने उनके साथ लंच भी किया, मीटिंग भी की। तो उसके बारे में क्या प्रोग्रेस हुई है और सरकार इस मामले में कहां तक पहुंची?

चौथा सवाल यह है कि इन्फिलट्रेशन जो हो रहा है उसके लिए सरकार ने क्या स्टैप्स लिए हैं?

पांचवा सवाल यह है कि अभी बीच में कश्मीर ऐडवाइजरी कमेटी बनी जो पैदा होने से पहले मर गई। एक मीटिंग उसने की, उसके बाद उसका नाम ही नहीं सुनाई दिया। वह जिन्दा है या अधमरी हो गई है या बिल्कुल ही खत्म हो गई है? होम मिनिस्टर बताएं कि उस कमेटी का क्या हुआ? वह क्यों बनाई गई थी और उसको भंग क्यों किया गया और अगर भंग नहीं किया गया है तो उसमें क्या काम हो रहा है?

अंत में मेरी अपनी तरफ से यह सलाह है कि अगर इस कश्मीर के मसले को हल करना है तो सबसे पहले वहां का जो लोकल ऐडमिनिस्ट्रेशन है- चाहे वह सिपाही हो, चाहे इंस्पेक्टर हो, चाहे तहसीलदार हो, चाहे बी०डी०ओ० हो, चाहे हवलदार हो-- उसको आप कॉन्फिडेंस में लीजिए। उसको बताइए कि आप

[श्री गुलाम नबी आज़ाद]

हिंदुस्तानी हैं, उसको आप पाकिस्तानी मत कहिए वरना आपके हाथ कुछ नहीं आएगा। उसको आप हिंदुस्तानी होने का जज़्बा दीजिए और उसको कान्फिडेंस में लीजिए और उसका इस्तेमाल कीजिए क्योंकि उन्हें मालूम है कौन चोर है, कौन डकैत है, कौन मिलिटेंट है, कौन सस्पैक्ट है, कौन क्लियर है। यहां से पुलिस वगैरह के भेजने से कुछ नहीं होगा।

मेरी दूसरी सलाह यह है कि जो लोकल पोलिटिकल पार्टीज़ बरसों से, आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद से वहां काम कर रही हैं, उन लोकल पार्टीज़ को भी आप कॉन्फिडेंस में लीजिए और उनके साथ बातचीत करके इस मसले को हल करने की कोशिश कीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

डा० रत्नाकर पाण्डेय (उत्तर प्रदेश): माननीय उपसभाध्यक्ष जी, एक बहुत ही गंभीर मसले की ओर मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। हमारे लैफ्टिनेंट जनरल देशपांडे साहब को समय से पहले ही उनके पद से हटा दिया गया है। मान्यवर, यह राष्ट्रीय महत्व का प्रश्न है इसलिए मैं इसे उठाना चाहता हूं। लैफ्टिनेंट जनरल को समय से पहले हटाना... (व्यवधान)

श्री महेन्द्र सिंह लाठर (हरियाणा): पाण्डेय साहब ने पार्लियामेंट को मज़ाक बना रखा है। जब चाहते हैं खड़े हो जाते हैं। अभी यहां इतना महत्वपूर्ण डिस्कशन हो रहा है... (व्यवधान)

डा० रत्नाकर पाण्डेय: वी.पी० सिंह की सरकार का जो यह रवैया है वह तानाशाही रवैया है ... (व्यवधान)

श्री मोहम्मद अफजलउर्फ भीम अफजल (उत्तर प्रदेश): वाईस चेयरमैन साहब, आप कैसे इजाज़त दे रहे हैं इनको ... (व्यवधान) तानाशाही तो आपने मचा रखी है।

डा० रत्नाकर पाण्डेय: देशपांडे के संबंध में हिंदुस्तान के अखबारों में जो समाचार छपा है... (व्यवधान)

उपसभाध्यक्ष (श्री भास्कर अन्नाजी मासोदकर) बैठ जाइए।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): Let us go on with the Kashmir issue. It is a very serious issue.

डा० रत्नाकर पाण्डेय: सेना में यह हस्तक्षेप बंद करिए वरना इससे सेना का मनोबल गिरेगा।

श्री महेन्द्र सिंह लाठर: मुझे बहुत अफसोस है कि जिस शांति के साथ हमने अहलुवालिया साहब को सुना, जिस पेशेंस के साथ हमने आज़ाद साहब को सुना तो जो हमारे भाई अपोज़ीशन में बैठे हैं क्या इनका यह फर्ज़ नहीं बनता कि वे हम लोगों को शांति से सुनें? हमें भी बोलने का अख्तियार है, हमें भी राइट है, हम भी इस हाउस के अंदर बोल सकते हैं। मैं सारे हाउस से अपील कर रहा हूं कि मैं काश्मीर के मसले को किसी पार्टी विशेष का मसला नहीं मानता, यह देश का मसला है। लेकिन जो तक़रीरें अहलुवालिया साहब ने और आज़ाद साहब ने की, उनमें सिवाय पार्टी पोलिटिक्स की बू आती है, और कुछ नहीं आता। मुझे बहुत अफसोस है कि बजाय इसके कि उनके कुछ सुझाव आते इस मसले को हम कैसे हल करें, काश्मीर के लोगों का दिल कैसे जीतें, उनका मेन स्ट्रीम में कैसे मिलाएं, इस बारे में उनका केवल एक ही सुझाव आया और वह सुझाव यह है कि जब यहां गवर्नमेंट टूट जाएगी और कांग्रेस सरकार बन जाएगी तो कश्मीर का मसला हल होगा यही एक सजेशन उन्होंने दिया। उन्होंने हमारी

पार्टी को अटैक किया, उन्होंने गवर्नमेंट पर अटैक किया, जाती तौर पर प्राइम मिनिस्टर पर अटैक किया, स्टेट मिनिस्टर साहब बैठे हैं, उन पर अटैक किया। इन बातों से काश्मीर का मसला हल होने वाला नहीं है। कौन जिम्मेदार है काश्मीर के लिए? 1947 की बात की आज़ाद साहब ने जब हमारे देश की बहादुर फौजें जिनके बारे में आज न जाने क्या कुछ उन्होंने कहा और एक मैंबर साहब ने कहा कि आपकी फोर्सेज ने, जैसे कि इनकी फोर्सेज वह नहीं हैं, हमारी ही फोर्सेज हैं, 1947 के अंदर जब पाकिस्तान के घुसपैठिए हमारे काश्मीर के अंदर घुस गए थे, उन्होंने हमारे ऊपर हमला किया था, तब हमारी बहादुर फौजें इस पोजीशन में थीं कि उन सारे पाकिस्तान के गुंडों को निकालकर बाहर फैंक देते तो वह कौन सी ताकत थी जिसने सीज़फायर का हुक्म दिया था? सोचिए, अगर वह सीज़फायर नहीं हुई होती, वह पाकिस्तान के पास हमारा टुकड़ा न होता तो आज यह प्राबलम हमें न भुगतनी पड़ती।

दूसरी बात भी आप सोचिए कि किसने धारा 370 बनाई? मैं पार्टी पोलिटिक्स में नहीं पड़ना चाहता, मैं एक हिन्दुस्तानी के नाते बोल रहा हूं कि 370 धारा जो संविधान में डाली गई क्या उससे हिन्दुस्तान से काश्मीर अलग नहीं हुआ? शुरू से ही यह धारा चलती रही और काश्मीर का मसला हमेशा हमेशा के लिए उठता रहा। हमारे देश के अंदर एक नहीं दो दो प्रधान मंत्री थे मुझे आप बताइए किसी मुल्क के बारे में जहां दो दो प्रधान मंत्री होते हैं। लेकिन हमारे मुल्क में रखे गए। काश्मीर को अलग रखने के लिए। क्या यह गलती आपसे नहीं हुई? मैं पंडित नेहरू की इज्जत करता हूं, सारा देश उनकी इज्जत करता है। उनसे भूल हुई। इंटरनेशनल प्रेशर में हुई चाहे शेख अब्दुल्ला के कारण हुई, लेकिन आज सारा देश उस का खामियाजा भुगत रहा है।

मैं प्रधान जी आपसे कहना चाहता हूं कि गलतियां उन्होंने ही नहीं कीं, 1947 से गलती चली आ रही है। हमने भी गलतियां कीं। मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं सारे देश के नेताओं को जिन्होंने इस देश को जोड़ने के नाम पर इसका बंटवारा किया, इसको बांटते चले गए। यहां पर मज़हब के नाम पर इस देश का बंटवारा किया। जात-पात के नाम पर बंटवारा हुआ, रीजन के नाम पर बंटवारा हुआ और भाषा के नाम पर बंटवारा हुआ और आज मुझे यह कहने में झिझक नहीं हुई कि आज जरिवेशन के नाम पर बंटवारा हुआ। इस देश का बंटवारा कर रहे हैं इस देश के नेता। इसके लिए हम सब जिम्मेदार हैं। अपने अंदर झांककर देखिए। जो सियासी लोग हैं, उन्होंने ही देश की हालत आज यह बनाई है। दूसरों को शिक्षा देने की बजाए अपने आपको रिफ़ार्म करो। अगर मैं अपने आपको सुधार लूं तो।

So our country will be less by one scoundrel. We are all naked under the clothes. We are not well-wishers of this country. You are talking of politics. Your country is going to be broken.

SHRI RAJUBHAI A. PARMAR (Gujarat): Mr. Lather, "our country" not "your country".

श्री महेन्द्र सिंह लाठर: मैं बहुत सेंटीमेंटल बात कर रहा हूं। आज काश्मीर में क्या हो रहा है, सुनिए बताता हूं। काश्मीर के अंदर बेगुनाह लोगों को मारा जा रहा है। लेकिन जम्मू काश्मीर के सो-कॉल्ड लिबरेशन फ्रंट वाले पोस्टेज स्टैम्प्स इश्यू कर रहे हैं। चार-चार कलर का पोस्टेज स्टैम्प निकल रहा है। वहां

[श्री महेन्द्र सिंह लाठ]

पर मजहब के नाम पर अनन्तनाग का नाम इस्लामाबाद रख दिया गया है। वहां की इकोनोमी जो कि टूरिज्म पर डिपेंड करती थी वह आज जीरो हो गयी है। आज जो कश्मीर की हालत है उसके लिए हम सब जिम्मेदार हैं किसी एक को ब्लेम देने की आवश्यकता नहीं है। मैं कहना चाहूंगा कि असेम्बली को भंग करना गलत था और फिर भंग कर दिया तो एक कंटरोवर्सियल गवर्नर को अपाएंट करना गलत था। और अगर अपाएंट कर दिया तो फिर उसको हटाना गलत था। पहले कश्मीर का मसला हल करने का काम फर्नांडीज साहब को सौंपा गया लेकिन पता नहीं क्यों उनसे वापस ले लिया गया। यह मेरी गवर्नमेंट ने किया, मैं इसको क्रिटीसाइज कर रहा हूं। आज कोई नेता, कोई पार्टी ऐसी नहीं है जो बोल्ड स्टैप ले सके। मुझे यह कहने में कोई झिझक नहीं है कि काम चलाऊ और वक्त टपाऊ वाली सरकारें अभी तक चलती रही है और चल रही हैं। उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी इजाजत से यह कहना चाहूंगा कि अहलूवालिया साहब ने यह बात कही है कि हमारी बहनों पर वहां पर अत्याचार हुए जो पुलिस ने किये या हमारी फ़ौज के कुछ आदमियों ने किये। मैं इसको कंडम करता हूं और जहां-जहां इस प्रकार के अत्याचार होते हैं बेइन्साफ़ी होती है मैं उनको कंडम करता हूं और करूंगा, सारा हाऊस भी कंडम करेगा लेकिन क्या यह उचित है, देश के हित में है कि सारी आर्म्ड फ़ोर्स को गंदा कहा जाए? ऊ अपनी बहादुर फ़ौज को मुबारकबाद देना चाहता हूं कि वह सिल्वर लाइनिंग है देश के लिए, वह एक उम्मीद है। हमारी फ़ौज वह फ़ौज है, जब जब पाकिस्तान ने हमला किया उसने मुंह तोड़ जवाब दिया। यह वह फ़ौज है जिसने एक भी गोली चलाये बिना 90,000 हथियारबंद-पाकिस्तान फ़ौज के घुटने टिकवा दिये यह बंगला देश में हुआ आप अपनी फ़ौज को कंडम कर रहे हैं। क्या ऐसा करने से, क्या फ़ौज को कंडम करने से कश्मीर का मसला हल कर सकते हैं? क्या आप उनके हौसले बुलन्द कर रहे हैं? क्या वी०पी० सिंह की सरकार उनकी क्रिटिसिज्म करने से चली जायगी? क्या आंखें बंद करने से बिल्ली भाग जायेगी? मुझे बड़ा अफ़सोस है कि ऐसी बातें कही जा रही हैं। मैं कभी-कभी बोलता हूं इस हाऊस के अंदर लेकिन यह मेरी आत्मा की आवाज है।

जो अभी कह रहे थे कि सारा कसूर इसी सरकार का है तो जुलाई 1989 का जो न्यूजट्रैक है उसको उठाकर अगर आप देखें तो आपको पता लगेगा कि कश्मीर की उस वक्त क्या हालत थी। यह सारा बेमतलब है। आपको मजहबी ताकतों को कंट्रोल करना पड़ेगा। मैंने इसी हाऊस में पहले भी कहा था और एक शेर सुनाया था कि

> मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना,
> हिन्दी हैं हम, वतन है हिन्दुस्तां हमारा।

आज के दिन वह बात नहीं है। आज के दिन क्या बात है? आज के दिन हम हिन्दू हो सकते हैं, आज के दिन हम मुसलमान हो सकते हैं, सिख हो सकते हैं, ईसाई हो सकते हैं लेकिन हम हिन्दी नहीं हैं। हम नेशन नहीं बन पाये, हम राष्ट्र नहीं बन पाये उसके बिना हम सब लोग जिम्मेदार हैं। लेकिन कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। फिर भी यह देश चले जा रहा है। फिर भी यह देश आज तक खत्म नहीं हुआ।

श्री शिव प्रताप मिश्र (उत्तर प्रदेश): न खत्म होगा।

श्री महेन्द्र सिंह लाठर: खत्म नहीं होगा इसका कारण है कि जब-जब क्राइसेज आते हैं इस देश पर, जब-जब

हमारे ऊपर हमला होता है, हम पर अटैक किया जाता है तो सारा देश एक नेशन के तौर पर उभर कर खड़ा होता है। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। थोड़ी सी बात थी जब पाकिस्तान ने हमारे ऊपर तोपें चलाई, कुछ जगहों पर हमला किया और यहां पर बहस हुई उस इशु को लेकर तो मुझे बड़ी खुशी है कि सबसे पहले लीडर आफ़ द अपोजिशन ने, उधर से सब लोगों ने खड़े हो कर यह कहा कि इस मसले पर जब कि देश को खतरा है तो हम सब गवर्नमेंट के साथ हैं। हम सब मुकाबला करेंगे इकट्ठे होकर। हम सब इकट्ठा होकर उसका मुकाबला करेंगे। हमारा राष्ट्र, हमारा नेशन, तब बनता है जब क्राइसेज आते हैं। बजाय इसके कि हम आपस में पोलिटिकल तकरार में पड़े, हमें एक होकर रहना चाहिये। कितने अफसोस की बात है कि एक ऐसा प्रान्त है जहां हम जाकर बस नहीं सकते हैं, जहां प्रापर्टी नहीं खरीद सकते और एक प्रान्त से दूसरे प्रान्त में दुकान खरीद कर दुकानदारी नहीं कर सकते। हिमाचल प्रदेश में भी ऐसा ही है, काश्मीर में भी ऐसा ही है और मैं समझता हूं कि अन्य भी प्रान्त होंगे। क्या हमने इन बाधाओं को हटाने की कोशिश की है कि हम सब प्रान्तों में जहां जाना चाहें, रहें? हमारा देश इतना बड़ा देश है। दुनिया के सबसे ज्यादा मुसलमान हमारे देश में रहते हैं, इसका हमें फक्र है। फिर काश्मीर हमसे अलग क्यों हो? क्या हमारी गवर्नमेंट ने कोशिश की कि काश्मीर के मुसलमानों के रिश्ते-नाते यहां के लोगों के साथ हों? क्या उनको यहां पर नौकरियां देने की कोशिश की गई है, बिजनस करने के लिए मौका दिया गया है? क्या हमने कोशिश की कि यहां के लोग वहां जाकर बसें? क्या हमने मिलन और आने-जाने का माहौल बनाया है? हमने काश्मीर को शुरू से ही अलग रखा ताकि हिन्दुस्तान के लोग वहां नहीं बस सकें। क्या आपने कभी सुना है कि उत्तर प्रदेश हिन्दुस्तान का अटूट हिस्सा है? क्या आपने कभी सुना है कि आन्ध्र प्रदेश भारत का अटूट हिस्सा है और ये अलग नहीं हो सकते हैं। लेकिन क्या कारण है कि हमारे प्रधान मंत्री से लेकर नीचे तक, चाहे वे पंडित नेहरू थे, शास्त्री जी थे, चाहे मोरारजी देसाई थे, सभी बार बार यही दोहराते रहे हैं कि काश्मीर भारत का अटूट हिस्सा है। हमें यह दोहराने की जरूरत क्यों पड़ी? किसी और प्रान्त के लिए हम यह बात क्यों नहीं दोहराते हैं? बीज हमने बोया है, फसल भी हम को काटनी पड़ेगी। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। इसको हमें नेशनल मसला मान कर वहां के लोगों का दिल जीतना चाहिये। हमें आपस में आना जाना चाहिए, उनके साथ रिश्ते नाते करने चाहिए, हम वहां बिजनेस करने जाएं और वहां के लोगों को यहां नौकरियां दी जायें। ऐसा माहौल बनना चाहिए। हम मजहब के नाम पर इस देश का दुबारा बंटवारा नहीं हवने देंगे। कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि फौज ज्यादती करती है। अगर देश के टुकड़े होते हैं तो उसको रोकने के लिए फौज को अगर कुछ ताकत का इस्तेमाल करना पड़े तो वह भी करना पड़ेगा। अब मजहब के नाम पर इस देश का बंटवारा नहीं होगा।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): Hanumantha Raoji. How much time you want? We have a discussion on Sri Lanka at 4 o'clock. Unless the House thinks... (*Interruptions*).

SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN (Tamil Nadu): We want the discussion at 4 o'clock.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): There is a suggestion that we can finish this.

SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN: We object to it because this debate has been going on for three or four days. (*Interruptions*). You have to take up Sri Lanka.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): What does the Leader of the House say? (*Interruptions*).

THE LEADER OF THE HOUSE (SHRI M. S. GURUPADASWAMY): We may go by the consensus of the House. But I would like the debate on this motion to be finished also. If you can take it up even after the Sri Lanka debate and finish it, I have no objection.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): After Sri Lanka, you want this?

SHRI M. S. GURUPADASWAMY: I want this to be done.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): What is the consensus of the House?

SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN: Sir it is listed at 4 o'clock.

SHRI YASHWANT SINHA (Bihar): You have not followed what the Leader of the House suggested. He has said, take up Sri Lanka, finish it and then take up Jammu and Kashmir after that.

SHRI JAGESH DESAI: It may be 6 o'clock then.

SHRI YASHWANT SINHA: Let us sit up after that. (*Interruptions*). It is not our sacred duty to adjourn at 6 o'clock.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): Mr. Rao, you please finish by 4 o'clock, and we will take up Sri Lanka at 4.00 P.M. And then we will see.

SHRI MOTURU HANUMANTHA RAO (Andhra Pradesh): Mr. Vice-Chairman, Sir, on behalf of my party, I support both the Resolution and the Bill, but at he same time I do it with reluctance, reluctance because the Resolution approving President's proclamation under article 356 should have been brought out as a constitutional amendment or as a bill regular after convening the Parliament. (*Interruptions*)

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): Would the Members maintain silence because it is a serious problem?

SHRI MOTURU HANUMANTHA RAO: The second thing is, giving special powers to the Army is a draconian step. There is no doubt about it. Even though it is a draconian step, I stand to support it in the special circumstances under which we are functioning now. Right across the border, a country is seeing to it that its interference is there and people are penetrating into our country after getttng training there. All these things are happening. Under these circumstances, perhaps it is inevitable that we resort to such draconian steps but at the same time I must caution our Government to see that the atrocities that are reported already are not repeated in future. My hon. friend, Mr. Ahluwalia, was narrating, in detail, the story of so many atrocities and if they are true, really they are unbelievable, they are very painful, they are shocking to any civilised mind and we should all stand in condemnation of them. But at the same time we should also see to it that the entire Army is not responsiblt for it; certain criminal elements from amongst the security men have done those things and for that, we should not condemn the entire Army which is discharging its duty, doing

some creditable service to our country. I am glad to hear that the Governor himself has not turned a blind eye to this. On the other hand, certain steps were taken to check such atrocities; some people were suspended and some were court-martialled. All these things are happening. Like that, some assurance is there from the Administration that such things would not be repeated. Secondly, I would like to say about the living conditions. Things are improving now in Kashmir, they are improving because of the stern steps taken by the Administration there. And because of that, most of the terrorist elements are arrested and some of them are eliminated. Though most of the JKLF leaders have been arrested, the other wing Mujahideens, which stands for the merger of Kashmir into Pakistan is in operation. So, that danger is there and still the danger of penetration is also there. That is exactly why these draconian powers to be resorted to. It is exactly why we should also see to it that stern steps are proceeded with otherwise there is every danger of making things worse. Another aspect is, a huge quantity of armaments was captured by the Army. That is also a good feature. 400 AK 47 guns, 400 machineguns, 120 rockets and about 700 anti-personnel mines....

[The Vice-Chairman, Prof. Chandresh P. Thakur (in the Chair)]

are captured. Perhaps there are more of such arms. We should see that all those arms are captured. These things have to be attended to and we should see that the stern action is continued. It is also true that under the previous administration the role of the Kashmiri population was considered to be almost anti-national. With such an approach alienation took place That is also there. But fortunately things are improving and a better climate has been created now. That is exactly why we should see to it that a political approach also is taken up immediately. A positive direction should be there. The struggle of the Kashmiri people is to retain direction should be there. The struggle of tht Kashmiri people is to retain their individuality, to retain their identity. That has been their struggle. If that is so, we should also see to it that the identity of the Kashmiri population is preserved and certain steps are taken to see that such an assurance is given to the people of Kashmir. Precisely at this time it is very unfortunate that one political party is campaigning for the deletion of Article 370 from the Constitution. It is really unfortunate that such a step is proposed. It would certainly strengthen the hands of separatists and it would be giving a handle to them, if we continue this campaign like this. So I request that our BJP friends should not continue this propaganda for the deletion of Article 370. It would be a harmful step. It would help disintegration rather than integration. That is exactly why all these things should be taken care of and now that a better climate is there. we must see to it that positive political steps are taken to bring about a real solution to the problem. Here our friends have been saying that under this Prime Minister if anything bad happens, he would be held responsible. Who is responsible for all these forty years? What was happening when the previous Prime Minister was there, when our national flag was pulled down and Pakistani flag was raised on August 15? Under whose premiership were we there at that time? So don't forget all those things and don't think you can blame the present Government for all the evils that have developed all along. Only the culmination point has reached now and we are now dealing with that development. You cannot say that people have started running away now. People have not started running away now to other places. They have been running away all the time. Because of the opportunistic policies that were pursued by the previous Government so

[Prof. Chandresh P. Thakur]
many things have happened and so many things have developed and now we are facing a situation like this. So, forgetting all those things, putting all the blame on the new Government which has come into power only nine months back, is very bad. And our friends also must realise the truth. So, many refugees are there now. Thousands of migrants are there now. They are all suffering. Proper relief must be given to them. We must immediately see to it that all the Kashmiri migrants are taken care of. About 10,000 NGOs are also there among them. All these people should be taken care
4.00 P.M. of by the administration now. So, if all these steps zare taken now, I think the prevailing situation in Kashmir can be bettered and we can work out a proper solution also to the problem. If all of us are so seriously concerned about Kashmir, about preserving Kashmir, about retaining it in our country, and if we consider it as a paradise and do not want to make it a hell, then we must see that all these positive steps that are taken by the national Front Government are supported by all of us. We should also see to it that the National Front Government takes it as a warning that the atrocities that have been committed up till now are not repeated. Otherwise, it would only help in alienating the Kashmiri population from our integration movement. Therefore, we must see that such atrocities such inhuman things, are not committed there.

With these words, I conclude. Thank you, Sir.

SHORT DURATION DISCUSSION SITUATION IN SRI LANKA

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. CHANDRESH P. THAKUR): Now, we will take up the Short-Duration Discussion on the situation in Sri Lanka... (*Interruptions*)...

SOME HON. MEMBERS: What about this? ... (*Interruptions*)....

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. CHANDRESH P. THAKUR): We have agreed that at 4 o'clock we will take this up and, after that, we will discuss the Resolutions relating to Kashmir.

SHRI JAGESH DESAI (Maharashtra): Provided this is completed before 6 o'clock. We will not sit after that... (*Interruptions*)...

THE VICE-CHAIRMAN, (PROF. CHANDRESH P. THAKUR): It is not in my hands; it is in the hands of the House... (*Interruptions*)...

SHRI V. GOPALSAMY (Tamil Nadu): Sir, the Business Advisory Committee has decided that we should sit upto 5 p.m. and beyond 6 p.m. as and when necessary ... (*Interruptions*)...

THE LEADER OF THE HOUSE (SHRI M. S. GURUPADASWAMY): Sir, may I say one thing? ... (Interruptions)...

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. CHANDRESH P. THAKUR): The only thing that can be done is that the Minister of State for Home Affairs should keep sitting here till then or return at 6 o'clock to see what the House decides. Yes, Mr. Gopalsamy, you start now... (Interruptions)...Yes Mr. Gopalsamy, you start now. You have got six minutes. I know you can speak for several days on this.

SHRI V. GOPALSAMY: Sir, the Business Advisory Committee has decided and all the Members also have agreed that the House should sit beyond 6 o'clock. Everybody agreed that we should sit beyond 6 o'clock so that we could get more time. Therefore, it was decided to take this up at 4 o'clock in the evening... (*Interruptions*)...

THE VICE-CHAIRMAN, (PROF. CHANDRESH P. THAKUR): The Business Advisory Committee has allotted two hours for the subject and you are the first speaker. You may enjoy